A Daily News Magazine
इंदौर
बुधवार, 25 फरवरी, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 145, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

एआई की बुद्धिमत्ता और हमारी मूर्खताएं

अरुण कुमार त्रिपाठी

भगवती चरण वर्मा की कहानी है 'वसीयत'। उसमें पंडित चूड़ामणि मिश्र के परिवार के लोग जीते जी उनकी उपेक्षा करते हैं लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत धन के लालच में वसीयत पढ़े जाते समय प्रेम और सम्मान का दिखावा करते हैं। जिस उत्तराधिकारी की आलोचना होती है वह कुढ़ता है और जब कुछ मिल जाता है तो वह प्रशंसा करने लगता है। बाद में वसीयत में पंडित तोते के स्वर में अपने शिष्य जनार्दन जोशी से कहते हैं तुम मूर्ख हो और मैं पंडित। कहीं ऐसा न हो कि होमो सेपियन्स की मानव प्रजाति अपने निधन के बाद जो वसीयत छोड़ जाए उसको लेकर उसकी संतानें कुछ वैसा ही नाटक करें और जो नैतिकता की बात करे उसे बुद्धू बता दिया जाए।

इजराइल के मशहूर इतिहासकार युआल नोवा हरारी अपनी पुस्तक नेक्सस में कहते हैं कि हमारी प्रजाति बहुत बुद्धिमान है। क्योंकि उसने बेइंतहा तरक्की की है। लेकिन वह मूर्ख भी है क्योंकि वह अपने विनाश के उपकरण लगातार जमा करती जा रही है। वे कहते हैं कि जर्मनी ने एक अधिनायकवादी उपकरण खड़ा किया और तकरीबन एक करोड़ लोगों की जान ली। आखिर में वह खुद भी धराशायी हो गया। लेकिन अब विनाश के उपकरण सार्वभौमिक हो गए हैं। वे मानव के नियंत्रण से बाहर निकलने को छटपटा रहे हैं। सर्वसत्तावाद सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में पैदा हुई लोकतंत्र की लहर को शांत करता हुआ झूठ, अनैतिकता, सत्तालोलुपता, अफवाह, दुर्भावनापूर्ण सूचनाएं, युद्ध और विनाश के नए औजारों को बांटते हुए नई सृष्टि का सृजन कर रहा है। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संपन्न सभ्यता नए किस्म की मूर्खताओं की ओर अग्रसर हो रही है।

जो लोग दूसरों को मूर्ख और स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझते हैं वे कितने किस्म की मूर्खताएं करते हैं उसकी तमाम कहानियां हमारी लोककथाओं में बिखरी पड़ी हैं। जैसे तीन जगह गंदगी लगने वाली कहानियां। उसकी एक झलक हाल में दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मिट 2026' में दिखाई पड़ी। जो सम्मेलन एआई से जुड़े मानव प्रजाति के गंभीर सवालों पर चर्चा के लिए आयोजित हुआ था और जिस पर भारतीय मीडिया में तमाम पन्ने और घंटे खर्च भी किए वह कुल मिलाकर कुछ नेताओं के अहंकार और कुछ संस्थाओं के झूठ और मूर्खताओं का आयोजन बनकर रह गया। संभव है कुछ अच्छी बातें हुई हों और कुछ सवाल उठे हों लेकिन बाहर जो संदेश गया वो यही गया कि गलगोटिया विश्वविद्यालय ने ओरियो (एक कुत्ता) नाम के एक रोबो को अपने केंद्र में विकसित बताकर दर्शाया और उसे आईटी मंत्री ने अपने ट्विट पर प्रचारित किया लेकिन बाद में जब चीन और नेटीजन ने यह असलियत उजागर की कि वह तो उनकी यूनीट्री नाम की कंपनी ने जीओ 2 नाम से विकसित किया है तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। यानी संसार को मूर्ख बनाने चले खुद ही मूर्ख बन गए।

एक घटना उस समय भी हुई जब ओपेन एआई के सीईओ आल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई का हाथ मिलवाने की कोशिश हुई और वे दोनों अपनी मुट्ठी ही बांधे रहे। उन्होंने ऊपर उठा हुआ हाथ एक दूसरे से नहीं मिलाया। वे दोनों कंपनियां एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हैं। पंडित चूड़ामणि मिश्र की संतानों की इस लोभ लालच, पाखंड और फरेब देखकर संदेह होता है कि वे वास्तव में पंडित जी की विरासत के साथ क्या करेंगे। एआई पर होने वाला यह पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नहीं था और न ही भारत ने इसमें कोई विशेष किस्म का नवोन्मेष किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 'मानव' संबंधी जुमले के माध्यम से उन नैतिक सवालों को उठाने की एक हद तक कोशिश की जो पहले उठते रहे हैं। जैसा कि हमारी सरकार हर चीज का लोकलुभावन संक्षेपीकरण करती है वैसा इस 'मानव' के मामले में भी था। यहां एम का अर्थ मॉरल से था, ए से अकाउंटेबिलिटी, एन से नेशनल सावरिनिटी, ए से एक्सेसबल/इनक्लूसिव और वी से वैलिड/ लेजिटिमेट का मतलब था। यानी यह सम्मेलन नैतिकता, राष्ट्रीय संप्रभुता, पहुंच, समावेशिता, वैधता पर केंद्रित था।

इस बारे में पहला सम्मेलन ग्रेट ब्रिटेन के ब्लेटचेली पार्क में 2023 में हुआ था। उसका जोर इस बात पर था कि एआई से पैदा होने वाले खतरे को संभालने के लिए कैसे वैश्विक सहयोग विकसित किया जाए। उसके बाद दूसरा सम्मेलन दक्षिण कोरिया के सिओल में 2024 में हुआ। उस सम्मेलन में 27 देश इस बात पर राजी हुए कि किस प्रकार एआई से सुरक्षित रहने के लिए एक नेटवर्क बनाया जाए जो कि मानक निर्धारित करे। तीसरा सम्मेलन पेरिस में 2025 में हुआ जहां पर यह तय किया गया कि किस प्रकार इसके एकाधिकार को रोकने के लिए पारदर्शी एआई आधारभूत ढांचा बनाया जाए। एआई के बारे में जो गंभीर सवाल हैं क्या वे हमारी चिंताओं में हैं या फिर हम अपने को तकनीकी महाशक्ति दर्शाने या महाशक्तियों के साथ खड़े होने की होड़ में उनकी उपेक्षा करते जा रहे हैं?

एआई के तमाम विशेषज्ञों ने जो सवाल और संदेह खड़े किए हैं उन पर हमें विचार करना ही चाहिए और उनके समाधान की दिशा में बढ़ना चाहिए। सबसे पहले ज्योफ्री हिल्टन जिन्हें एआई का जनक कहा जाता है उनकी चिंताओं को देखना चाहिए। हिल्टन ने साफ तौर पर अफसोस जताया है कि काश! मैंने यह आविष्कार न किया होता। यह मानवता के लिए खतरा है। क्योंकि एआई अगले 20 वर्षों मंज मानव जाति की बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ सकती है। यह शैतानी शक्तियो के हाथों में पड़ सकती है और इससे जैविक हथियार बनाए जाने, बड़े पैमाने पर विस्थापन, बेरोजगारी, सामाजिक अस्थिरता और मानव के नियंत्रण के बाहर होने का खतरा है। इसी तरह की चिंता एक और विशेषज्ञ योशुआ बेनजिओ ने भी जताई है। उनका कहना है कि इससे विनाशकारी खतरा है।

एआई से जुड़े नैतिक सवाल वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम में भी उठते रहे हैं। जैसे कि बेरोजगारी, असमानता, मानवता, कृत्रिम मूर्खता, नस्ली रोबो, सुरक्षा, शैतानी शक्तियां, अनियंत्रण की चुनौती और रोबो के अधिकार। अभी एआई के बारे में जो समझाइश दी जा रही है वो यही है कि पहले भी जब नई मशीनें आई थीं तो इसी तरह के तर्क दिए जाते थे कि उनसे मानव का रोजगार छिन जाएगा। लेकिन सभ्यता चली जा रही है और कोई खास दिक्कत नहीं आई। जब एआई मनुष्य ने बनाया है तो वह उसे नियंत्रित करना भी चाहेगा और अगर चाहेगा तो वह नियंत्रित कर लेगा।

(फेसबुक वॉल पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

ईश्वर,
ध्यान देना...
जब खड़ा होना पड़े मुझे
तो अपने अस्तित्व से ज़्यादा जगह न घेरूँ।
मैं ऋग्वेद के चरवाहों कि करुणा के साथ कहता
हूँ–
मुझे इस अनंत ब्रह्मांड में
मेरे पेट से बड़ा खेत मत देना,
हल के भार से अधिक शक्ति,
बैल के आनंद से अधिक श्रम मत देना।
मैं तोलस्तोय के किसान से सीख लेकर कहता हूँ
:
मुझे मत देना उतनी ज़मीन
जो मेरे रोज़ाना के इस्तेमाल से ज़्यादा हो,
हद से हद एक चारपाई जितनी जगह
जिसके पास में एक मेज़-कुर्सी आ जाए।
मुझे मेरे ज्ञान से ज़्यादा शब्द,
सत्य से ज़्यादा तर्क मत देना।
सबसे बड़ी बात
मुझे सत्य के सत्य से भी अवगत करवाना।
मुझे मत देना वह
जिसके लिए कोई और कर रहा हो प्रार्थना।

- प्रशस्ति पाठक

आरक्षण 200 साल भी देना पड़े तो सही

● संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले- समाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए ● भागवत बोले- ऐसे लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए सब है जायज ● कहा- उन्होंने दो हजार सालों तक भेदभाव सहा, फिर भी देश के साथ गद्दारी नहीं की

देहरादून (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज के एक हिस्से ने करीब दो हजार साल तक छुआछूत और भेदभाव सहा, लेकिन फिर भी उसने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए अगर दो सौ साल तक भी आरक्षण देना पड़े, तो समाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर अपने ही भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नुकसान भी सहना पड़े, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आरएसएस प्रमुख सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून में हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित 'प्रमुखजन गोष्ठी' में पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे।

कई राजनीतिक दल अपने मूल मार्ग से भटक गए

स्वतंत्रता के बाद कई राजनीतिक दल अपने मूल मार्ग से भटक गए। समाज की एकता ही व्यक्तियों और नेतृत्व को शक्ति देती है; समाज कमजोर होगा तो नेतृत्व प्रभावी नहीं रह सकता। सामाजिक शक्ति ही व्यक्तियों और नेतृत्व को बल देती है। यदि समाज में भेदभाव और विभाजन रहेगा तो राष्ट्र की शक्ति कमजोर होगी।

● **भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक हैं** – इस दौरान भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक हैं और उनकी रगों में एक ही खून बहता है। हिंदू बनने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, देश के प्रति निष्ठा ही पर्याप्त है और आज जिनका विरोध है, उन्हें भी कल जोड़ना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत नेतृत्व, उच्च सैन्य तैयारी और निरंतर प्रशिक्षण अनिवार्य हैं। अग्निवीर योजना एक प्रयोग है। अनुभवों के आधार पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकता हो तो सुधार एवं परिमार्जन पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि सेना की क्षमता, अनुशासन और दीर्घकालिक मजबूती बनी रहे। राष्ट्र के भाग्य निर्माण में समाज की केंद्रीय भूमिका होती है। समाज मजबूत और संगठित होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी सशक्त होगी।

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

सरसों पर मिलेगा भावांतर, किसानों की पांच योजनाएं 5 साल तक रहेंगी जारी

भोपाल (नप्र)। एमपी कैबिनेट ने किसानों के लिए पांच योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी है। साथ ही सरसों पर भावांतर देने का फैसला किया है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के प्रावधानों के परिवर्तन की स्वीकृति एमपी कैबिनेट ने दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में वंदे मातरम् गायन के साथ कैबिनेट की बैठक हुई।

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। कैबिनेट में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। किसान कल्याण वर्ष में कृषकों के लिए लगभग 10,500 करोड़ रुपए की पांच योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी गयी है।

कृषि विकास की दक्षता वृद्धि, विभिन्न कृषि घटकों की प्रभावकारिता को बढ़ाने, दोहराव से बचने अभिसरण सुनिश्चित करने

तथा राज्य सरकार को योजना बनाने में लचीलापन प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित है। इसके तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परियोजना तैयार कर क्रियान्वित की जाती है। इस योजना को आगामी 5 वर्षों 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 2008.683 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वहीं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 2393 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गयी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के लिए 3285 करोड़ 49 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किए जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 1011 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी। वहीं, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल सीड के लिए 1793 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी मिली है।

सरसों के लिए भावांतर योजना की स्वीकृति

इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने सरसों के लिए भावांतर योजना की स्वीकृति दी है। प्रदेश में सरसों भावांतर योजनान्तर्गत 23 मार्च से 30 मई 2026 तक सरसों का विक्रय राज्य की अधिसूचित मंडियों में किया जाएगा। एमपी की मंडियों में 14 दिवस के सरसों के विक्रय मूल्य के भारित औसत के आधार पर सरसों के मॉडल रेट की गणना की जाएगी।

सीएम योगी को मिल गई बड़ी सफलता

● **जेवर एयरपोर्ट को मिले 4458 करोड़ के दो प्रोजेक्ट**

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज (एससीई) के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता उत्तर प्रदेश में संस्थागत क्षमता और नीतिगत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया है। साथ ही इकोसिस्टम के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष न सिर्फस्टडी विजिट्स व लीडरशिप डेलिगेशन का आयोजन करेंगे, बल्कि ट्रेनिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों का खाका तैयार कर उसे लागू भी कराएंगे।

● **जेवर एयरपोर्ट बनेगा नॉर्थ इंडिया का कार्गो हब**– एमओयू के अनुसार, एआई सैट्स जेवर एयरपोर्ट परिसर में एक अत्याधुनिक कार्गो कैंपस का निर्माण करेगी। यह कार्गो कैंपस न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एयर फ्रेट और लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस परियोजना से निर्यात–आयात गतिविधियों को गति मिलेगी, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ होगा। एमओयू के दूसरे प्रमुख निवेश के तहत नोएडा का एयर कैटरिंग किचेन शामिल है।

भोपाल में कांग्रेस की किसान चौपाल में राहुल गांधी बोले–

मोदी ने अमेरिका से की देश बेचने की डील

भोपाल (नप्र)। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एपस्टीन और अडाणी के केस का दबाव है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया।

राहुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोल रहे थे। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में किसान चौपाल बुलाई थी। इस दौरान राहुल ने कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मैं चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात रखना चाहता था।

राहुल ने कहा- मैंने लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की बात रखी थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीनी घुसपैठ हुई थी तो उन्हें हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी हैं। उन्होंने देश को बेच दिया। किसानों के साथ छल किया। मोदीजी रोज उठकर चाय पर बात करते थे, तो क्या देश को बेचने की बात करते थे।

हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की। मुझे रोका गया। फिर शुरू की, फिर रोका गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप टैरिफ को रद्द करेंगे और रद्द कर दिया।

राहुल गांधी ने थपथपाई यूथ कांग्रेस की पीठ, कार्यकर्ताओं को बताया बब्बर शेर, बोले– 'किसी से डरने की जरूरत नहीं

राजधानी के जवाहर चौक पर सजी किसान महाचौपाल में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी। राहुल ने दिल्ली में गिरफ्तार हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 'बब्बर शेर' बताया और कहा कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मंच से हुंकार भरते हुए कहा, शांतिपूर्ण विरोध हमारा अधिकार है और सच्चाई हमारे साथ है। मोदी सरकार युवाओं और किसानों की आवाज दबाने के लिए तानाशाही पर उतारू है, लेकिन हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे।

खड़गे बोले– मोदी गिड़गिड़ाते हुए ट्रंप के पैरों पर गिरे

खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ट्रंप ने खुद कहा सिंदूर ऑपरेशन को मैंने रोका। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कहकर मैंने रोका। ये बात ट्रंप ने कही है। पीएम मोदी ने गिड़गिड़ाते हुए, ट्रंप के पैरों पर गिरकर कहा मैं ऑपरेशन रोकता हूं। ऑपरेशन सिंदूर रोककर आपने बहुत बड़ी गलती की। आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो।

खड़गे ने कहा- कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो मरेंगे। संविधान को जिंदा रखना है। आपको लड़ना है। अमेरिका के पास बहुत बड़ी जमीन है लेकिन 3 परेंसट लोग किसान हैं। हमारे पास हमारे देश में 65 परसेंट खेती पर डिपेंड हैं। हमारा किसान जो पैदावार कर रहा है, उसे मोदी खत्म कर रहे हैं।

बीजेपी का पलटवार– 'राहुल के नाम में रार, हुड़दंग और लफंगाई है': मंत्री सारंग

कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के नाम की नई परिभाषा गढ़ते हुए कहा कि 'रा' का मतलब रार, 'हु' का मतलब हुड़दंग और 'ल' का मतलब लफंगाई है। सारंग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि खराब करने वाले राष्ट्रद्रोही कृत्य का समर्थन कर रहे हैं।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 25 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

नक्सलियों के गढ़ में एजुकेशन सिटी, लड़कियों को 1.5 लाख रुपए

● छत्तीसगढ़ बजट की बड़ी बातें, किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है। इस बार छत्तीसगढ़ के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की। इस बजट में लड़कियों के 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रुपये देने का प्रावधान भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में एजुकेशन सिटी बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। छत्तीसगढ़ के बजट की

थीम संकल्प है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान इसके सभी अक्षरों का मतलब भी सदन को समझाया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य विधानसभा में 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 9,450 करोड़ रुपये, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए 3,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बस्तर में इंद्रावती नदी पर मतनार और देउरगांव बैराज बनाने के लिए बजट में 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये जगह कभी नक्सलियों का गढ़ कही जाती थी। बस्तर इलाके के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक इवेंट्स के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

जल्द सुलझ जाएगा असम अरुणाचल सीमा विवाद

● उठाया गया बड़ा कदम, दोनों राज्यों के बीच पहला सीमा स्तंभ स्थापित

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच पहले सीमा स्तंभ (पिलर) की स्थापना को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। हिमंत ने कहा कि स्पष्ट सीमाएं तेज विकास, बेहतर कानून-व्यवस्था और दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि असम सभी अंतर-राज्यीय मुद्दों

को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा नेएक्स पर पोस्ट में कहा कि नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में पहला सीमा स्तंभ स्थापित किया गया है। यह दोनों राज्यों के बीच लंबित विवादों को संवाद और सहयोग के माध्यम से हल करने की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है। सीमा स्तंभ की स्थापना असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सहयोग और विश्वास का प्रतीक है। यह कदम उन सीमावर्ती गांवों में स्थायी शांति और प्रशासनिक निश्चितता लाएगा, जो कई दशकों से अस्पष्टता से प्रभावित थे। इससे पहले असम और अरुणाचल ने नामसाई घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हिमंत ने कहा कि इस समझौते में स्थानीय समुदायों की भलाई को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए श्रेय दिया।

अब 'केरलम' के नाम से जाना जाएगा केरल

मोदी कैबिनेट ने नाम बदलने की दे दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई पीएमओ बिल्डिंग सेवा तीर्थ में मंगलवार को हुई पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसी क्रम में मोदी कैबिनेट ने केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम अप्रैल-मई में होने वाले केरल विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है। केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को एकमत से एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने की अपील की गई थी। विधानसभा के प्रस्ताव के बाद मंगलवार को हुई यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने को मंजूरी दे दी गई है। केरल विधानसभा ने दूसरी बार प्रस्ताव पास किया था क्योंकि गृह मंत्रालय ने कुछ टेक्निकल बदलावों का सुझाव दिया था। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन चाहते थे कि केंद्र सरकार संविधान के आठवें शेड्यूल में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिणी राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम कर दे। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य को मलयालम में 'केरलम' कहा जाता है और मलयालम बोलने वाले समुदायों के लिए एक संयुक्त केरल बनाने की मांग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही जोरदार तरीके से उठी है।

मेक इन इंडिया साकार करेगी ओलेक्ट्रा की 1,085 इलेक्ट्रिक बस

भोपाल/हैदराबाद। भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को 1,085 इलेक्ट्रिक बसों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) मिला है। यह ऑर्डर तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) द्वारा ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से दिया गया है। यह परियोजना कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड

(सीईएसएल) के नेतृत्व में चल रही पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत है। बसें हैदराबाद में संचालित होंगी। कंपनी तेलंगाना को 12-मीटर लो-फ्लोर एसी और नॉन-एसी बसें उपलब्ध कराएगी। इन बसों में एयर सस्पेंशन, हाई-कैपेसिटी लिथियम-आयन बैटरी और 250 किमी से अधिक रेंज होगी। 45 मिनट में फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी रहेगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर स्पेस दिया गया है। एमडी महेश बाबू ने कहा कि यह ऑर्डर 'मेक इन इंडिया' संकल्प को मजबूती देगा और राज्य में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

● 26/11 जैसे हमले का है प्लान, सैफुल्लाह कसूरी ने खाई कसम

पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ने फिर दी धमकी

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी के एक नये वीडियो से पता चलता है कि वो समुद्र के रास्ते भारत पर आतंकी हमला करने की योजना बना रहा है।

सैफुल्लाह कसूरी उन लोगों में शामिल है जिन्हें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। वो कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी है।

उसने 2008 के मुंबई हमले की याद दिलाते हुए एक चेतावनी दी है जिसमें उसने कहा है कि समुद्री रास्ते से भारत में फिर से 26/11 जैसा हमला किया जाएगा। उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि 2026 में समुद्री रास्ते से होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सैफुल्लाह कसूरी कह रहा है कि जमीन, हवा या समुद्र में दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वह इस आतंकी हमले को अल्लाह की मर्जी बताता है और कसम खाता है कि पाकिस्तान जल्द ही सभी स्ट्रेटेजिक डोमेन पर कंट्रोल कर लेगा। खुफिया सूत्रों से यह जानकारी मिली है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये बयान 26/11 मुंबई हमलों जैसे समुद्री हमले की पहले से चेतावनी हैं, जिन्हें 2008 में लश्कर ने रचा था और अरब सागर के रास्ते अंजाम दिया था। पहलगाम आतंकी हमले में कसूरी सीधे तौर पर शामिल था जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। जिसमें आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गये थे।

कसूरी को पाकिस्तान की सेना का है साथ

वीडियो में कसूरी खुलेआम कह रहा है कि उसे पाकिस्तान की सेना का साथ हासिल है। पाकिस्तानी सेना के तालमेल के साथ वो काम कर रहा है। जिससे एक बार फिर से साबित होता है कि पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना एक ही साथ काम करते हैं। शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से ये धमकियां पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के फिर से इकट्ठा होने का इशारा है। वहीं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीडियो का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आतंकियों में फैले खौफ के बीच गुर्गों का हौंसला बढ़ाना है। हालांकि भारत अब अरब सागर के चप्पे चप्पे पर चौकसी रखता है और 26/11 जैसे हमले करना मुश्किल है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने महर्षि विटीलिगो रिसर्च सेंटर और डायबिटीज एंड फुट केयर सेंटर का किया शुभारंभ

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने इंदौर में महर्षि विटीलिगो रिसर्च सेंटर और महर्षि डायबिटीज एंड फुट केयर सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि उक्त सेंटर उच्च और आधुनिक तकनीक से लैस है, जहां सफेद दाग का संपूर्ण उपचार होने के साथ-साथ पैर के अल्सर घाव का बेहतर तरीके से उपचार होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने महर्षि विटीलिगो रिसर्च सेंटर और डायबिटीज एंड फुट केयर सेंटर का अवलोकन किया और चिकित्सकों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सेंटर के संचालक सफेद दाग विशेषज्ञ डॉ. संजय दुबे और

मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. अनुपमा दुबे को शुभकामना दी। कार्यक्रम में भारतीय जल सेना प्रमुख एडमिरल श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया सहित चिकित्सक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

दिलीप बिल्डकॉन का फर्जी चेक बनाकर राशि आहरण करने का प्रयास करने वाले आरोपी को हुई सजा

भोपाल। मनोज त्रिपाठी संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 24/02/2026 माननीय न्यायालय श्री अतुल सक्सेना 23वे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, द्वारा फर्जी चेक बनाकर राशि आहरण करने वाले आरोपी शौकीन्द्र कुमार पिता धर्मपाल को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 420 सहपठित धारा 511 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड एवं धारा 474 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसटीएफ भोपाल श्री आकिल खान द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

घटना का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना एसटीएफ भोपाल को दिलीप बिल्डकॉन के अध्यक्ष भारत जी द्वारा एक लिखित शिकायत की गई थी कम्पनी द्वारा पूर्व में जारी किये गये चेक क्रमांक 492400 राशि 3000/- जो उसकी कम्पनी के कर्मचारी अंकुर कुमार को दिया गया था उक्त चैक की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्लोनिंग कर 10 करोड़ की राशि का चैक तैयार कर देव कन्स्ट्रक्शन के नाम से दिनांक 27/02/2020 को केनरा बैंक जिला मुजफ्फनगर उत्तर प्रदेश में आहरण हेतु प्रस्तुत किया। जब उक्त चैक की जॉच क्लीरिंग शाखा के द्वारा की गई तो मालूम हुआ है कि उक्त क्रमांक का चैक पहले ही आहरण हो चुका है। जिस कारण बैंक द्वारा चैक का भुगतान रोक दिया गया एवं संबंधित बैंक की शाखा को सूचना दी गई। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना एसटीएफ के अपराध 144/2020 धारा 420, 511, 474 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य, दस्तावेजों एवं न्यायादृष्टात से सहमत होते हुए आरोपी शौकीन्द्र कुमार को उक्त धाराओं में दोषसिद्ध का निर्णय पारित किया गया है।

पिछड़ा वर्ग में कितने मुसलमान ये आंकड़े लाइए

सुप्रीम कोर्ट ने पसमांदा की याचिका पर जताई हैरानगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट पसमांदा मुस्लिमों को अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में शामिल करने की याचिका का परीक्षण करने पर राजी हो गया है। याचिका में पसमांदा मुसलमानों को शिक्षा और नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण की बात कही गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी भी जताई कि ऐसी डिमांड दूसरे गरीब मुसलमानों के लिए क्यों नहीं की गई है। द टेलीग्राफ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पसमांदा मुसलमानों के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग की

अर्जी याचिकाकर्ता मोहम्मद वसीम सैफी ने दी थी। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने सख्त लहजे में पूछा कि दूसरे गरीब मुसलमानों की कीमत पर आप शायद खुद को (पसमांदा) प्रमोट करना चाहते हैं। कोई आंकड़ा है कि पिछड़ा वर्ग से असल में कितने मुसलमान हैं।

● **5 जजों की बेंच इस मामले में करेगी सुनवाई**-एडवोकेट अंजना प्रकाश ने कोर्ट से यह अपील करते हुए कि इस मामले को 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका के साथ टैग कर दिया जाए। आंध्र सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दी है, जिसमें राज्य सरकार के मुस्लिमों के लिए 4 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को विचार के लिए 5 जजो की संवैधानिक पीठ के समक्ष भेज दिया। पसमांदा फारसी शब्द है, जिसका मतलब है जो पीछे छूट गया है। इसे आमतौर पर मुसलमानों में वंचित तबकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पसमांदा मुसलमान शब्द का पहला इस्तेमाल 1998 में अली अनवर अंसारी ने किया था, जिन्होंने पसमांदा मुस्लिम महाज की स्थापना की थी।

शंकराचार्य को गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट में याचिका लगाई

● बोले-अजय पाल साजिश रच रहे, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ

वाराणसी (एजेंसी)। बच्चों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उन्हें डर है कि प्रयागराज पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी। कल यानी सोमवार को पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस से शंकराचार्य और उनके करीबियों की जानकारी जुटाई। सूत्रों के मुताबिक, प्रयागराज पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ करने उनके आश्रम पहुंच सकती है। गिरफ्तारी भी कर सकती है।

ओडिशा-झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद

● **पश्चिम बंगाल एसआईआर:** सुप्रीम कोर्ट बोला-इनका खर्च चुनाव आयोग उठाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमीशन दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड-ओडिशा के सिविल जजों की मदद ले सकता है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 28 फरवरी

को बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पोल पैनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। इससे पहले 20 फरवरी को, पश्चिम बंगाल सरकार और ईसी के बीच चल रही खींचतान से निराश होकर कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस में पोल पैनल की मदद के लिए मौजूदा और पूर्व जिला जजों को तैनात करने का निर्देश जारी किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर में बताया था कि 80 लाख लोगों के क्लेम से निपटने के लिए 250 डिस्ट्रिक्ट जजों को लगाया है।

● **सुप्रीम कोर्ट ने किया अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल**- सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किया कि बंगाल में सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल में वोटरों को फाइनल लिस्ट में शामिल माना जाएगा। यह शक्तियां कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली हैं।

● द केरल स्टोरी 2 को लेकर हाई कोर्ट के जज बोले-मैं आज फिल्म देखूंगा

लोगों की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' को दिए गए क्लियरिफिकेशन को लेकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सवाल किया। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इस बात पर जोर दिया कि जब फिल्म केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को सांप्रदायिक नजरिए से दिखाती है, तो सीबीएफसी की अहम भूमिका होती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस तीन याचिकाओं पर विचार कर रहे थे जिनमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और इसके क्लियरिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि यह आशंका जताई गई थी कि इससे सांप्रदायिक दंगा भड़क

सकता है। जस्टिस थॉमस ने कहा, केरल इतना धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां पूर्ण सद्भाव है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब किसी घटना को पूरे राज्य में घटित होते हुए दिखाया जाता है तो क्या होता है। इससे गलत संकेत मिलते हैं और यहां तक कि भावनाओं को भी भड़काया जा सकता है और ऐसे में सेंसर बोर्ड की भूमिका सामने आती है। जस्टिस थॉमस ने कहाकि फिल्म के टाइटल में राज्य का नाम शामिल है, केरल के लोगों की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जस्टिस थॉमस ने कहा, आम तौर पर मैं किसी फिल्म में दखल नहीं देता। लेकिन मैं कल बुधवार को फिल्म देखूंगा।

गंदे पानी व सुविधाओं को लेकर घेराव

इंदौर। शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की मौजूदगी में झोन क्रमांक 13 बिलावली पर कांग्रेस नेताओं और क्षेत्रीय रहवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वार्ड क्रमांक 74 से 78 तक गंदे पानी की आपूर्ति, जल जमाव और अधूरी विकास कार्यों को लेकर झोन अधिकारियों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान चौकसे ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही से जनता की जान जोखिम में नहीं डालने दी जाएगी। उन्होंने आशंका जताई कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हालात भागीरथपुरा जैसे बन सकते हैं। क्षेत्रवासियों ने नई पाइप लाइन डालने, दूषित पानी की आपूर्ति बंद करने, अधूरी सड़कों को पूरा करने, सड़क चेम्बर कार्य शुरू कराने, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट चालू करने और नियमित कचरा उठाव की मांग उठाई।

तेज रफ्तार आयशर ने युवती को रौंदा

इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में नौकरी पर जा रही युवती की जान चली गई। तेज रफ्तार आयशर वाहन ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चौधरी कॉलोनी निवासी आरती पिता फूल सिंह रोज की तरह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए निकली थी। वह मोंटी फूड प्रोडक्ट कंपनी की चॉकलेट फैक्ट्री में कार्यरत थी। प्रभुतोल कांटा के पास पहुंचते ही पीछे से आए बेकाबू आयशर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि आरती दूर जा गिरी और उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस से उसे एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

स्कूल ड्रेस की दुकान में भीषण आग

इंदौर। निहालपुरा स्थित दशरथ मार्केट में मंगलवार सुबह एक स्कूल ड्रेस की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग मार्केट की दूसरी मंजिल पर स्थित दुकान नंबर 214 में लगी थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही इंदौर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मोती तबेला फायर स्टेशन से एसआई संतोष दुबे के नेतृत्व में दमकल वाहन तत्काल रवाना किया गया। सुबह करीब 6 :55 बजे मिली सूचना के बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में लगभग 8 हजार लीटर पानी का उपयोग किया गया। दमकल कर्मियों की सतर्कता से आग को दूसरी मंजिल तक ही सीमित रखा गया, जिससे मार्केट की अन्य दर्जनों दुकानें सुरक्षित बच गईं। हालांकि दुकान संचालक दिनेश पिता गंगाराम की दुकान में रखी बड़ी संख्या में स्कूल ड्रेस और अन्य कीमती सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय दुकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

कार में 'एमडी' क्राइम ब्रांच ने दबोचा

इंदौर। शहर में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी कार के जरिए मादक पदार्थ 'एमडी' की सप्लाई करने की फिराक में था। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 10 ग्राम एमडी बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग एक लाख रुपये आंकी गई है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच टीम संदिग्धों की तलाश में गश्त कर रही थी। इसी दौरान रुद्र एजेंसी बिल्डिंग के पास एक कीया कार संदिग्ध हालत में खड़ी दिखी। पुलिस वाहन देखकर चालक भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन मुस्तैद टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सूरज मिश्रा निवासी नंदबाग बताया। तलाशी के दौरान कार की ड्राइविंग सीट के पास बने आर्म रेस्ट बॉक्स में पारदर्शी पन्नी में छुपाकर रखी गई एमडी बरामद हुई। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बाहरी क्षेत्रों से सस्ते में ड्रग्स लाकर इंदौर में ऊंचे दामों पर बेचता था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नेटवर्क की जांच की जा रही है।

थानों की रैंकिंग में विजयनगर अव्वल

इंदौर। अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने एक नई पहल के तहत जनवरी माह की थानों की रैंकिंग जारी कर दी है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य पुलिस थानों के कामकाज को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाना है। इस रैंकिंग में विजयनगर थाना अव्वल तो सेन्ट्रल कोतवाली थाना सबसे फिसड्डी साबित हुआ। इस व्यवस्था के तहत सभी 32 थानों के कार्यों का हर महीने तय मापदंडों पर आकलन किया जाता है। संबंधित जोन की डीसीपी की अध्यक्षता में गठित समिति थानों की अपराध नियंत्रण क्षमता, मामलों के निराकरण, जन संतुष्टि, नवाचार और अन्य प्रशासनिक कार्यों के आधार पर मूल्यांकन करती है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले थाना प्रभारी और उनकी टीम को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरी ओर, कमजोर प्रदर्शन वाले थाना प्रभारी और स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि प्रशिक्षण के बाद भी कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो सख्त विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

बीफार्मा स्टूडेंट की सड़क हादसे में मौत

इंदौर। सोमवार दोपहर खुड़ैल रोड पर हुए सड़क हादसे में बीफार्मा के एक छात्र की मौत हो गई। एक ट्राले ने देवगुराडिया रोड पर बाइक को टक्कर मार दी। घायल छात्र को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। टक्कर के बाद लोगों ने ट्राला चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वह इंडेक्स कॉलेज में बीफार्मा फाइनल ईयर का छात्र था।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान जुनेद (24) पुत्र जावेद निवासी काजी पलासिया के रूप में हुई है। सोमवार दोपहर उसकी बाइक को ट्राले ने टक्कर मारी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद जुनेद को तत्काल एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वह दवा बाजार की एक मेडिकल दुकान पर जाता था और खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहता था। अप्रैल में उसकी डिग्री आने वाली थी। परिवार में उसके दो छोटे भाई हैं और पिता खेती करते हैं।

तेज डीजे बजा, साउंड सिस्टम और वाहन जब्त

इंदौर। खजराना थाना क्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मोबाइल के डेसिबल मीटर ऐप से ध्वनि स्तर की जांच की। आवाज निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने पर डीजे वाहन और साउंड सिस्टम जब्त कर आयोजक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय समय के बाद डीजे संचालन पर प्रतिबंध है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि मप्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में खजराना टीआई मनोज सिंह सेंधव के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। मुखबिर की सूचना पर टीम वेलोसिटी टॉकीज के पास पहुंची, जहां बिना अनुमति डीजे संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान ध्वनि स्तर तय मानक से अधिक मिला। पुलिस ने मौके से डीजे संचालक करण गौड़ निवासी चंदन नगर के खिलाफ कार्रवाई कर साउंड सिस्टम और वाहन जब्त कर लिया।

हाई कोर्ट में नहीं खुली धार भोजशाला की एएसआई सर्वे रिपोर्ट, सुझाव मांगे

आपत्तियों और सुझावों पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी

इंदौर। धार की विवादास्पद भोजशाला को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से एक बड़ा अपडेट सामने आया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा भोजशाला पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों की ओर से बताया किया उन्हें सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां मिल चुकी है। एएसआई की रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने सार्वजनिक नहीं करने से इंकार किया। भोजशाला पर एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट पर इंदौर कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों की ओर से बताया कि उन्हें सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां मिल चुकी है। जिसके एएसआई की उस रिपोर्ट को कोर्ट ने सार्वजनिक नहीं किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को आदेश जारी करते हुए कहा कि वे एएसआई की 98 दिन तक चली वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्तियां, सुझाव अगली सुनवाई में दे सकते हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च 2026 तय की है। जिसमें सभी जवाबों पर विचार किया जाएगा।

सर्वे रिपोर्ट खुली कैसे- सुनवाई शुरू होते ही डिवीजन बेंच ने पूछा कि रिपोर्ट पहले से याचिकाकर्ताओं और इंटरवीनर को कैसे मिल गई और खुल भी गई! जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोर्ट के समक्ष खोलने के निर्देश दिए थे। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि रिपोर्ट पहले ही कोर्ट में पेश हो चुकी थी और उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, कोर्ट ने आगे की प्रक्रिया तय करते हुए कहा कि जिन पक्षों को सर्वे रिपोर्ट मिल चुकी है, वे दो सप्ताह के अंदर अपने दावे, आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराएं। इसके बाद मामले की सीधे अंतिम सुनवाई की जाएगी। प्रशासनिक जज विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, आशीष गोयल, विनय जोशी सहित अन्य पैरवी कर रहे हैं।

मार्च में भोजशाला पर फैसला- हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वकील विनय जोशी के मुताबिक, कोर्ट से सुनवाई के लिए अगले महीने की तारीख दी है। हम अपने लिखित जवाब कोर्ट में पेश करेंगे। जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जो भी निर्णय होगा, उसका पालन करेंगे। उल्लेखनीय है कि भोजशाला विवाद पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने व्यापक सर्वे कराने के आदेश जारी किए थे। करीब 98 दिन तक एएसआई की टीम ने सर्वे किया। इस दौरान 3-डी स्कैनिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर), फोटोग्रामेट्री और स्थापत्य अध्ययन किया गया।

570 में से 118 भवनों की गहन जांच 'कैग रिपोर्ट' में अनियमितता उजागर

औद्योगिक इकाइयों में ग्राउंड कवरेज स्वीकृत सीमा से अधिक

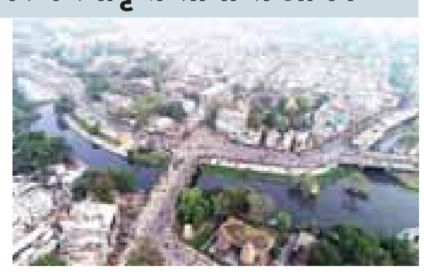

इंदौर। 2018-19 से 2022-23 के बीच इंदौर में कुल 24,608 भवन अनुमतियां जारी हुईं। 'कैग' ने इनमें से 570 मामलों का सैंपल चुना और 118 भवनों की विस्तृत ऑडिट जांच की। जांच में स्कूल, प्रोफेशनल ऑफिस (क्लिनिक, नर्सिंग होम, ऑफिस), औद्योगिक इकाइयों सहित विभिन्न श्रेणियों में नियमों के उल्लंघन सामने आए। ऑडिट में पाया गया कि कई स्कूलों में निर्धारित पार्किंग स्पेस उपलब्ध नहीं कराए गए। ओपन स्पेस और सेट-बैक मानकों का पालन भी नहीं हुआ। यह सब भवन अनुज्ञा की शर्तों में स्पष्ट होने के बावजूद उपयोग की अनुमति दे दी गई। क्लिनिक, नर्सिंग होम और अन्य प्रोफेशनल ऑफिस के मामलों में सामने आया कि पार्किंग या सर्विस एरिया के लिए स्वीकृत बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का उपयोग अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। औद्योगिक इकाइयों में ग्राउंड कवरेज स्वीकृत सीमा से काफी अधिक पाया गया। कई मामलों में आंतरिक सड़क, पार्किंग और ओपन स्पेस के प्रावधान मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं थे। इससे फायर सेफ्टी और आपातकालीन पहुंच जैसे मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि भवन अनुमति जारी होने के बाद फील्ड-लेवल निगरानी तंत्र प्रभावी नहीं रहा।

वर्षवार जांच इस प्रकार रही- 2018-19:30 केस, 2019-20 : 12 केस, 2020-21 : 23 केस, 2021-22 : 24 केस और 2022-23 : 29 केस। गौरतलब है कि छोटी आवासीय इकाइयों और छोटी दुकानों को जांच के दायरे में शामिल नहीं किया गया। कॉलोनी परमिशन के 265 मामलों में से केवल 68 की ही जांच हुई।

सैंपल प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियां- जांच में कुछ उदाहरण इस प्रकार सामने आए। इंदौर इंडिया आई केयर क्लिनिकः स्वीकृत 67% के बजाय 85% ग्राउंड कवरेज। 279 वर्गमीटर की अनुमति के विरुद्ध 450 वर्गमीटर निर्माण। हॉल मार्क स्कूल- 30% स्वीकृत ग्राउंड कवरेज के स्थान पर 45% निर्माण। 590 वर्गमीटर के बजाय 700 वर्गमीटर निर्माण। माही ई-आर्ट (आवासीय)-50% अनुमति के मुकाबले 100त्न तक निर्माण।

निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल- 'कैग' ने निष्कर्ष में कहा है कि स्वीकृत भवन उपयोग की शर्तों के उल्लंघन के बावजूद समय पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। औद्योगिक भवनों में अनुमति के बाद निगरानी तंत्र कमजोर रहा। निरीक्षण की कमी के कारण स्वीकृत और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर लंबे समय तक अनदेखा रहा। रिपोर्ट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और संबंधित स्थानीय निकायों की मॉनिटरिंग प्रणाली में गंभीर कमियां रेखांकित की हैं।

युवती को छह माह लिव-इन में रखा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया

परिचितों के घर और कई होटलों में ले जाकर संबंध बनाए

इंदौर। सहेली के चचेरे भाई ने एमबीए की छात्रा को छह माह तक लिव इन में रखा। इस दौरान वह शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। युवती की शिकायत पर अजाक्स पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर उदयपुर निवासी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2021 में वह सहेली के साथ कोचिंग जाती थी। वहीं उसकी पहचान सहेली के चचेरे भाई से हुई, जो अपनी बहन को कोचिंग छोड़ने और लेने आता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई और जुलाई 2021 से संपर्क बढ़ा। छात्रा का आरोप है कि दिसंबर 2021 में मुलाकात के बाद युवक ने शादी का वादा किया और जनवरी में परिचित के घर बुलाकर संबंध बनाए। इसके बाद वह उसे विभिन्न होटलों में ले जाता रहा।

छह साल तक भरोसा दिलाता

पीड़िता का कहना है कि आरोपी बीच-बीच में अपने गांव चला जाता था, लेकिन वापस आकर फिर संपर्क करता और शादी की बात दोहराता। वर्ष 2024 में वह राजस्थान चला गया और संपर्क कम कर दिया। कुछ समय बाद वह दोबारा इंदौर आया और फिर से साथ रहने का आश्वासन दिया। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक वह श्रद्धा सबुरी कॉलोनी में किराए के मकान में उसके साथ लिव-इन में रहा। 6 फरवरी को वह वापस चला गया और संपर्क तोड़ लिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

तात्कालिक विवाद में दो पक्षों में मारपीट

इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में तात्कालिक विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घुंसे चले। बीच बचाव करने आई महिला से भी युवकों ने मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीन युवकों सहित नाबालिग को हिरासत में लिया है। घटना जगदीश नगर गली नंबर 10 की है। रविवार रात करीब 12 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंती तो पता चला कि विवाद करने वाले युवक नशे की हालत में थे। घटना के दौरान रहवासियों ने एहतियात के तौर पर घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मारपीट में सभी को सामान्य चोट आई है। सोमवार को मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जगदीश नगर में रहने वाले हितेश मालवीय, रोशन यादव, मुन्ना शर्मा और नाबालिग को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार युवक प्राइवेट नौकरी करते हैं।

वीडियो वायरल की धमकी देकर वसूली

इंदौर। कनाड़िया इलाके में छात्र को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 17 हजार रुपए की मांग का मामला सामने आया है। वैभव नगर निवासी अभिसार कौल ने प्रथम पिता नरेन्द्र बिल्लोरिया निवासी प्रीति नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि उनका बेटा गर्वित पढ़ाई कर रहा है। आरोपी के पास गर्वित का सिगरेट पीते वीडियो है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह रुपए मांग रहा था।

छावनी में सड़क चौड़ीकरण से उलझन कोर्ट के दखल से निगम बैकफुट पर

मधुमिलन से छावनी वाली सड़क को 24 मीटर किए जाने पर विवाद

इंदौर। नगर निगम ने मधुमिलन चौराहे से छावनी पुल तक सड़क चौड़ी करने का काम फिलहाल टाल दिया। यह फैसला अदालत दखल के बाद किया गया। छावनी रोड इन दिनों शहर की नई राजनीति और प्रशासनिक बहस का केंद्र बन गया। 18 मीटर चौड़ी सड़क को 24 मीटर करने के फैसले के आधार पर बाधक निर्माण हटाने के नोटिस जारी होने के बाद क्षेत्र में असंतोष बढ़ा और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने नगर निगम ने नोटिस प्रभावहीन कर दिए हैं। लेकिन, लोग अभी असमंजस में ही हैं। कुछ दिन पहले सड़क पर सेंटर लाइन डाले जाने से रहवासियों को चौड़ीकरण की आशंका हुई। जोन-11 के भवन अधिकारी ने 24 मीटर चौड़ाई में आ रहे हिस्सों को हटाने के नोटिस जारी किए। इसके विरोध में कई प्रभावितों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। इस बारे में एडवोकेट जयेश गुरनानी का कहना है कि सालों पहले 18 मीटर चौड़ाई के हिसाब से भवन निर्माण की अनुमतियां दी गई थीं। जब निगम ने खुद नक्शा पास किया, टैक्स लिया और अब अचानक 24 मीटर का हवाला देकर नोटिस दे दिया, तो रहवासी कहां जाएं!

एक सड़क के दो मानक - इंदौर विकास योजना 2021 में इस मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर दर्शाई गई है। वहीं, पुराने रिकॉर्ड में 18 मीटर के आधार पर निर्माण अनुमति दी गई। यही विरोधाभास पूरे विवाद की जड़ है। कानून के मुताबिक बिना विधिक प्रक्रिया और अधिग्रहण के सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हो सकती है। अभिभाषकों का कहना है कि पूर्व में भी न्यायालय ने प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई से ठीक पहले निगम ने नोटिस को प्रभावहीन करने का निर्णय लिया और आश्वासन दिया कि आगे की कार्रवाई नियमों के तहत ही होगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मास्टर प्लान में शामिल किसी भी सड़क की चौड़ाई कम नहीं की जाएगी। अब जब बाधक मकानों पर दोबारा निशान लगाए जा रहे हैं तो एक बार फिर यह मामला उठ गया है।

24 फीट मानकर मार्किंग - नगर निगम ने पिछले सप्ताह फिर छावनी सड़क पर तोड़फोड़ की तैयारी कर ली थी। निगम की इस कार्रवाई से रहवासियों और दुकानदारों में आक्रोश है। रहवासियों की मांग है कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाई न जाए। यहां मधुमिलन चौराहे से जगन्नाथ धर्मशाला तक लगभग 870 फीट सड़क मास्टर प्लान योजना के अंतर्गत बनाई जाना है।

600 से ज्यादा मकान टूटेंगे - छावनी और सुभाष मार्ग के चौड़ीकरण में 600 से ज्यादा मकान बाधक हैं। छावनी सड़क पर 328 तो सुभाष मार्ग पर 304 मकान चिह्नित किए हैं। दोनों जगह मिलाकर 100 से ज्यादा मकान पूरे खत्म हो रहे हैं। दोनों ही जगह रहवासी सड़कों की चौड़ाई कम रखने की मांग कर रहे हैं। रहवासियों के साथ जनप्रतिनिधि भी छावनी सड़क की चौड़ाई कम करने की मांग उठा चुके हैं। विधायक गोलू शुक्ला और महापौर परिषद सदस्य मनीष शर्मा मामा ने भी मास्टर प्लान की सड़कों को लेकर हुई बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, लेकिन सहमति नहीं बन सकी थी।

बच्चा चोर की अफवाह पर महिला से मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने के लिए समझाया

इंदौर। शहर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में हीरानगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त रुबीना मिजवानी ने बताया कि 22 फरवरी की रात थाना क्षेत्र के रघुनंदन बाग इलाके में महिला अपने पति से विवाद के बाद नाराज होकर घर से निकल गई थी। वह नाले के किनारे अंधेरे में जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और शोर मचाते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि भीड़ ने महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। महिला किसी तरह वहां से निकलकर थाना हीरानगर पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच कर तीन आरोपियों देवेन्द्र परोले निवासी रघुनंदन बाग कॉलोनी, आरती राजपूत निवासी कबीटखेड़ी तथा आशा कौशल निवासी कबीटखेड़ीको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही क्षेत्र में लोगों को समझाइश दी गई कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कानून हाथ में न लें।

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बच्चा चोर जैसी भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं। यदि किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दें। किसी को रोकना, मारपीट करना या अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध है, और ऐसा करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर की लापता छात्रा दिल्ली स्टेशन पर मिली, मां की डांट से आहत हुई

इंदौर। इंदौर से लापता हुई 10वीं कक्षा की छात्रा रविवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित मिल गई। रेलवे पुलिस ने उसे स्टेशन परिसर में संदिग्ध अवस्था में घुमते देख पूछताछ के बाद परिजनों से संपर्क किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छात्रा की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही। छात्रा एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित कृष्णबाग कॉलोनी की निवासी है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर 12 बजे वह कोचिंग जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। चिंतित परिजनों ने उसी रात थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अगले दिन सामने आए सीसीटीवी फुटेज में वह पैदल जाते हुए दिखाई दी, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई थी। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज हो गई थी। गुस्से में उसने घर छोड़ दिया और अपने नाना के पास भोपाल जाने के लिए ट्रेन में बैठी, लेकिन गलती से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई। दिल्ली में वह स्टेशन पर इधर-उधर भटकती रही। खबर मिलते ही छात्रा के मामा दिल्ली रवाना हो गए हैं। छात्रा के पिता आटो चालक हैं और परिवार में एक छोटा भाई भी है।

'सेज' के छात्र की डूबने से मौत

खुडैल थाना क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए सेज यूनिवर्सिटी के बीए सेकंड ईयर के छात्र की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। छात्र अपने तीन दोस्तों के साथ मुहाड़ी फॉल घूमने गया था, जहां नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। घटना रविवार की है। मृतक का नाम सूरज पिता अशोक कुशवाह (20) निवासी वेंकटेश नगर है। वह फॉल के कुंड में नहा रहा था। इसी दौरान वह अचानक गहराई वाले हिस्से में पहुंच गया और डूब गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। अंधेरा होने के कारण रात में सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। सोमवार सुबह पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुंड से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। वह इंदौर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज से आने के बाद वह रेपिडो चलाता था। सूरज के पिता मुरैना में खेती करते हैं। कुछ समय पहले उसके छोटे भाई का भी निधन हो चुका है। परिवार में सूरज मझला बेटा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

कुछ ही घंटों में दो नाबालिगों को खोजा

इंदौर। गुमशुदा बच्चों की तलाश को लेकर पुलिस की सतर्कता एक बार फिर सफल रही। द्वारकापुरी थाना पुलिस ने महज कुछ घंटों में दो नाबालिग बालकों को खोजकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार, 22 फरवरी को 13 वर्ष 7 माह एवं 12 वर्ष के दो बालकों के लापता होने की सूचना मिली थी। बच्चों के अचानक गायब होने से परिजन काफी चिंतित और परेशान थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त शिवेन्दु जोशी के मार्गदर्शन में टीआई मनीष मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और संभावित स्थानों पर पूछताछ की। तकनीकी साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर कुछ ही घंटों में दोनों बच्चों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया।

संपादकीय

ट्रेड डील का क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा छेड़े गए टैरिफ वॉर को कानून अवैध ठहराने के बाद ट्रंप भले ही दूसरे देशों को धमकियां दे रहे हों, लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने के पहले ही अधर में फंस गई है। भारत सरकार ने इस डील पर अमेरिका से चर्चा को रोक दिया है। डील पर चर्चा के लिए भारत का एक उच्चस्तरीय प्रति निधिमंडल अमेरिका गया हुआ है। हालांकि इसे अभी लौटने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन संकेत साफ है कि भारत अब आगे के घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे ट्रंप प्रशासन टैरिफ पर अपनी नीति को किसी भी कीमत पर आगे जारी रखेगा। ऐसे में आगे क्या होगा, यह कहना अभी मुश्किल है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बनने की जानकारी देते हुए भारत पर लगे 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। साथ ही ये दावा किया था कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने पर रजामंदी दे दी है। इस 50 प्रतिशत टैरिफ में 25 प्रतिशत रेसिप्रोकेल टैरिफ था जबकि 25 प्रतिशत टैरिफ रूसी तेल खरीदी के लेकर दंडात्मक रूप से लगाया गया था। विगत शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को 6-3 के मत से गैरकानूनी घोषित किया, तो उसके तुरंत बाद ट्रंप ने दूसरे क़ानून (ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122) का सहारा लेते हुए नए सिरे से पहले 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने और फिर शनिवार को इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया। नया ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए लागू हो गया है। हालांकि ट्रंप ने मीडिया से यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टैरिफ को लेकर भारत के साथ हो रहे समझौते में 'कुछ भी नहीं बदलेगा और भारत भुगतान करना जारी रखेगा।' इधर भारत में इस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप भी जड़ दिया है। पार्टी ने इसे भारतीय किसानों के हितों के विपरीत बताते हुए देश भर में इसके खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ट्रेड डील ट्रंप के दबाव में और जल्दबाजी में हुई है। जबकि सरकार इस डील को भारत के हित में बता रही है। हालांकि कांग्रेस को इससे कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ट्रेड डील भारतीय किसानों के हितों को चोट पहुंचाएगी। इससे किसान सरकार से नाराज होंगे और उनका रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा। इससे कांग्रेस को कुछ राज्यों में सत्ता पाने अथवा सत्ता में लौटने में मदद मिलेगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस यह विरोध प्रदर्शन उन्हीं राज्यों में कर रही है, जहां जल्द चुनाव नहीं होने हैं। और जहां चुनाव अगले चार माह में होने हैं, वहां खास हलचल नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में यह रस्साकशी तब है कि ट्रेड डील का फाइनल ड्राफ्ट अभी सामने आया ही नहीं है। इसे 15 मार्च को सामने आना था, लेकिन नई परिस्थिति में यह कब आएगा, आएगा भी या नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे ट्रंप की किसी बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगला कोई भी कदम सोच समझ कर ही उठाया जाना चाहिए।

अविश्वास प्रस्ताव बनाम सब्सटेंसिव मोशन

नजरिया

अवधेश कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भारत की राजनीति ऐसी अवस्था में पहुंची है जिसकी पहले कल्पना नहीं थी। यह भारत के संसदीय इतिहास की अत्यंत गंभीर स्थिति है जब लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है तो उसके समानांतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन। राहुल गांधी के विरुद्ध सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सब्सटेंसिव मोशन लाने की मांग की है। भाजपा ने पहले राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात की थी किंतु लगता है गंभीरता से विमर्श करके सब्सटेंसिव मोशन की पहल की है। सब्सटेंसिव मोशन विशेषाधिकार हनन से ज्यादा गंभीर हो सकता है। सब्सटेंसिव मोशन स्वतंत्र मूल प्रस्ताव है जिसमें सांसद के विरुद्ध स्पष्ट आचरण या निर्णय सामने आता है। इस पर बहस और मतदान होता है तथा पारित होने पर सदन का अधिकारिक रुख और मत प्रकट होता है। यानी संबंधित सांसद का आचरण और चरित्र सांसद के अनुकूल है या नहीं, इन्हें सांसद होना चाहिए या नहीं, इन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने देना चाहिए या नहीं आदि आदि। इसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है और सदन की सदस्यता भी जा सकती है? चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की जा सकती है। तो इसे कैसे देखा जाए? राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस इस पर या प्रतिक्रिया स्वाभाविक है कि हम डरने वाले नहीं है। 24 दिसंबर, 2005 को लोकसभा के 10 और राज्यसभा के एक सांसद की सदस्यता कैसे गई थी? एक टेलीविजन चैनल ने स्टिंग किया और सांसदों पर धन लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगा। सब्सटेंसिव मोशन के तहत उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें आरोपों के उत्तर का भी अवसर नहीं दिया गया। इसमें मुख्य भूमिका कांग्रेस की ही थी।

अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में आना बंद कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद बहस और परिणाम तक लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो उन्होंने यह निर्णय किया । यही बात सांसद या विपक्ष के नेता पर लागू नहीं होती। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव या सब्सटेंसिव प्रस्ताव स्वीकृत होने के बावजूद संबंधित सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दिया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर 9 मार्च को बहस होने की संभावना है। यह देखना होगा कि सब्सटेंसिव मोशन स्वीकृत होता है या नहीं। चूंकि भाजपा नेतृत्व वाले राजग को बहुमत है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। यही बात सब्सटेंसिव मोशन के साथ लागू नहीं होता। बहुमत के आधार पर गठबंधन राहुल गांधी के विरुद्ध निश्चित मत और कार्रवाई तक का प्रस्ताव पारित कर सकता है। कांग्रेस के अंदर उनके समर्थकों में इससे कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। उल्टे वे यह कहते हुए प्रफुल्ल होते हैं कि एजेंडा तो राहुल गांधी ही सेट कर रहे हैं और वह सब्सटेंसी मोशन पर बहस भी उन्हीं के इर्द-गिर्द रहेगी। अगर सोच ऐसी हो तो कल्पना की जा सकती है कि राहुल गांधी और उनके इर्द-गिर्द के रणनीतिकार किस दिशा में जा रहे हैं। बजट सत्र आरंभ होने

के पहले दिन को छोड़कर आरंभ से अंत तक राहुल गांधी सदन के अंदर और बाहर सर्वाधिक चर्चा और बहस के विषय रहे। क्या इसे सही अर्थों में राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करना कहेंगे? लोकसभा में विपक्ष के नेता की दृष्टि से इसे बिल्कुल जायज माना जाएगा? क्या इससे राहुल गांधी अपने राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं?

किसी एक नेता के विरुद्ध कार्रवाई होगी तो लोगों में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो सकती है और अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। दूसरा पक्ष यह है जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अभियान चला उसका क्या? उनकी बेटी के सिविल सर्विस पास होने तक पर प्रश्न उठाने वाले कौन थे? कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा उनको लिखा गया पत्र देखिए, चरित्रहनन है। और आपने अविश्वास प्रस्ताव तक ला दिया । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट घेर कर कांग्रेस की महिला सांसद बैनर लिए खड़ीं थी। माहौल का ध्यान रखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा मैंने उनसे सदन में न आने का अनुरोध किया क्योंकि कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था। एपिस्टन फाइल को लेकर निराधार आरोप क्या चरित्रहनन नहीं है? इस फाइल में किसी का नाम आना उसके पाप में भागीदार का द्योतक नहीं हो सकता। एपिस्टन फाइल की मुख्य चर्चा अवयस्क बालक - बालिकाओं के साथ शर्मनाक यौनाचार के संदर्भ में है। यह जानते हुए कोई उसके संपर्क में है तोउसे दोषी माना जाएगा। जिस तरह राहुल गांधी और उनके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं उसे चरित्र हनन की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। संकेत में यह कहना कि प्रधानमंत्री दबाव में है क्योंकि अभी फाइल में माल बहुत है और अडाणी पर अमेरिका में केस हैं आदि आदि क्या है? यही बताने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री का दबाव है और इसीलिए वे देश का सौदा कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए ऐसी कठिन स्थिति पैदा करने की कोशिश है कि उन्हें फैसला लेने में ही समस्या हो। ओम बिरला यहां व्यक्ति नहीं लोकसभा अध्यक्ष जैसे गरिमापूर्ण पद पर हैं। हमारा व्यक्तिगत उनसे मतभेद हो सकता है, उनसे नापसंदगी भी होगी, पर पद का सम्मान करने और विश्वास करने का प्राथमिक दायित्व भी नेता और संसद न निभाएं तो इसे क्या कहेंगे? यह सब शर्मनाक है।

हालांकि राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव ने विश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किया। यह भी एक रणनीति होगी ताकि वे बोल सके कि हमने अध्यक्ष पद की गरिमा का ध्यान रख हस्ताक्षर नहीं किया।आपकी रणनीति हो सकती है कि किसी तरह उन्हें मनोवैज्ञानिक दबाव में रखो और अपना एजेंडासदन के माध्यम से प्रचारित और स्थापित करने की कोशिश करो। जब एक पक्ष सीमा का इस सीमा तक उल्लंघन करता रहेगा तो दूसरे पक्ष से भी प्रत्युत्तर उस रूप में आ सकता है। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा प्रस्तुत पुस्तक जिनमें नेहरू परिवार के चरित्र पर प्रश्न खड़े किए गए हैं उसी की प्रतिक्रिया में आया था। आपने लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया, प्रधानमंत्री का भी चरित्रहनन किया, देश के प्रति उनकी निष्ठा के विरुद्ध दुष्प्रचार किया तथा अंततः ऐसी स्थिति पैदा की किए हुए राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में भाषण नहीं दे सके तो आपके विरुद्ध भी सब्सटेंसिव मोशन आ गया। शीर्ष स्तर की राष्ट्रीय राजनीति का इस स्तर पर नहीं पहुंचना चाहिए था जहां प्रतिक्रिया देना कठिन हो जाए। आखिर रास्ता क्या है?

अगर राहुल गांधी के समर्थकों को गलतफहमी है कि चर्चा और बहस का एजेंडा सेट करना है बड़ी उपलब्धि है तो एसआईआर एवं चुनाव आयोग के संदर्भ में भी ऐसी ही स्थिति थी। उन्होंने अपनी ओर से पूरी तैयारी के साथ एसआईआर और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, बिहार में वोट अधिकार यात्रा की, चुनाव परिणाम आपके सामने है। महाराष्ट्र चुनाव में अडाणी मुद्दा उनके लिए सर्वोपरि था।परिणाम देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों का निलंबन तब किया जब वे बेल में जाकर लगातार अध्यक्ष की ओर कागज फेंक रहे थे, कोई आदेश या नियमन नहीं मान रहे थे। सामान्य सभा की भी अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति की ओर चिल्ला- चिल्ला कर कागज फेंका जाएगा तो उनके प्रति गुस्सा ही पैदा होगा और समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सदन संचालन के नियम और परंपरा हैं । इसको हर हाल में रौंदने को उतारू लोगों के विरुद्ध अध्यक्ष को फैसला करना ही पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस एक दिन भी सामान्य स्थिति पैदा नहीं होने देने पर उतारू है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति अभिभाषण से संबंधित मुद्दे पर किसी सत्र में भाषण नहीं दिया। वह एजेंडा लेकर आते हैं और उसे सदन में रखते हैं तथा अध्यक्ष के रोकने पर उन्हें आरोपित करते हैं। इस लोकसभा के पहले हाथों में संविधान की लाल किताब लेकर नारे लगाए गए। क्या यह आचरण उचित था? पहली बार कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा किया। इस तरह की सोच और व्यवहार में कोई लोकतांत्रिक रास्ता निकल नहीं सकता। यह कहना कठिन है कि सब्सटेंसिव मोशन से रास्ता निकल पाएगा। सच कहें तो सदन को तय करना पड़ेगा कि विपक्ष के इस तरह के नेता से कैसे निपटा जाए? नियम और परंपरा बनाने वालों ने ऐसे विपक्ष के नेता की कल्पना भी नहीं की होगी। आप एक बार रोकेंगे तो दूसरे तरीके से आ जाएंगे।

बदलती शीर्ष उच्चतर शिक्षा की नियामक व्यवस्था

शिक्षा प्रणाली

डॉ. सत्येन्द्र किशोर मिश्र

प्रोफेसर अर्थशास्त्र, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन के अगले पड़ाव में उच्चतर शिक्षा नियामक व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव को अग्रसर है। भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थान जहां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा शोध, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन का अभाव; स्वायत्तता तथा वित्तीयन में कमी से समस्याग्रस्त हैं। नियामक व्यवस्थाओं में नौकरशाही, भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टरराज, अक्षमता, गैरजवाबदेही, गलत कार्यप्रणाली जैसी ढ़ेरों समस्याएं, उच्चतर शिक्षा को खोखला कर रही हैं। उच्चतर शिक्षा नियामक व्यवस्था में सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), तकनीकी शिक्षा के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), तथा शिक्षक शिक्षा के नियामक तंत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) का सम्मिलन कर तथा इनसे संबंधित अधिनियमों को समाप्त कर 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (विभाशा) विधेयक 2025' के तहत् एकीकृत निकाय की स्थापना करने जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने हेतु उच्चतर शिक्षा में मौजूद गंभीर समस्याओं से निपटना जरूरी है, परन्तु देखना होगा कि प्रस्तावित व्यवस्था किस तरह तथा कितना कारगर होगी।

भारत के ग्यारह सौ से अधिक विश्वविद्यालयों तथा साठ हजार से अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों में चार करोड़ से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। उच्चतर शिक्षा नियामक निकायों की बहुलता तथा कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े होते रहे हैं। इनके द्वारा विशेष सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमिका निभानी थी। परन्तु समय के साथ ये संस्थाएं लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, गैरजवाबदेही, जड़ता तथां दोहरेपन जैसी समस्याओं से जकड़ गयीं; जिससे निगरानी प्रणाली, गुणवत्ता तथा मानक व्यवस्था में असंगतियां आयी; उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना मुश्किल हो गया। राज्यों के विश्वविद्यालय, जहां लगभग नब्बे फीसद विद्यार्थी पंजीकृत हैं, केन्द्र तथा राज्यों के नियम-कानूनों में उलझते रहे। समय के साथ उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ इनकी नियामक व्यवस्था में संस्थागत बदलाव की जरूरत है।

एनईपी में उच्चतर शिक्षा में बेहतर बदलाव हेतु दशकों पुरानी नियामकों की तिकड़ी को खत्म कर, एकीकृत उच्चतर शिक्षा नियामक व्यवस्था है। इसमे उच्चतर शिक्षा में शीर्ष नियामक के तौर पर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (विभाशा) के गठन के साथ ही विनियमन, अकादमिक गुणवत्ता तथा प्रत्यायन एवं मान्यता हेतु अलग-अलग स्वतंत्र स्तंभ होंगे। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत् उचचतर शिक्षा में विनियमन, मान्यता, वित्तीयन तथा अकादमिक मानक स्वतंत्र एवं सशक्त निकायों द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। एकीकृत नियामक व्यवस्था लालफीताशाही, भ्रष्टाचार तथा दखलंदाजी को समाप्त कर उच्चतर शिक्षा में स्वायत्तता एवं उत्कृष्टता को सुनिश्चित करेगी। केन्द्रं सरकार द्वारा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के तहत् यूजीसी, एआईसीटीई तथा एनसीटीई को एकीकृत निकाय में सम्मिलन कर शीर्ष निकाय विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना का प्रस्ताव है। तीन स्वतंत्र स्तंभों के अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में विनियमन, मानकों के समन्वय, अनुरक्षण तथा अनुपालन हेतु विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद्, सांस्थानिक प्रत्यायन ढ़ांचा विकसित करने हेतु विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद्, तथा उच्चतर अकादमिक मानक अवधारण हेतु विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद् की स्थापना का प्रावधान है। भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के जरिए सुधार प्रक्रिया अचानक नहीं आरंभ हुई, बल्कि उच्चतर शिक्षा नियामक संस्थाओं में सुधार की मांग बहुत पहले से थी। पूर्व में ही यूजीसी, एआईसीटीई तथा एनसीटीई की तिकड़ी को समाप्त करने की सिफारिश राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा की गयी थी। यशपाल समिति की रिपोर्ट (2009) में नियामक एजेंसियों की बहुलता से समन्वय की कमी और नीतिगत असंगति को सुधारने की बात थी। यशपाल समिति तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार यूजीसी की कार्यप्रणाली से उच्चतर शिक्षा में जवाबदेही तथा परदर्शिता तो नहीं आ सकी, स्वायत्तता अवश्य कमजोर हुई। प्रस्तुत विधेयक ऐसी कमियों को दूर कर उच्चत्तर शिक्षा एवं शोध में उत्कृष्टता, जवाबदेही, पारदर्शिता का बढ़ावा देने को कृत संकल्पित है। वर्ष 2018 में, सरकार द्वारा एचईसीआई ड्राफ्ट के जरिए यूजीसी को एक नये नियामक तंत्र में बदलने का प्रयास हुआ था, परन्तु बात आगे नहीं बढ सकी। एनईपी ने इस बदलाव को पुनः गति देते हुए विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के कामकाज को बेहतर बनाने हेतु नियामक व्यवस्था में सुधार की जरूरत समझते हुए विनियमन, मान्यता, फंडिंग और शैक्षणिक मानकों के लिए सरल परन्तु सुदृढ़ अलग-अलग निकायों की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया है।

परन्तु विधेयक के विरोध में भी आवाजे उठ रही है। प्रस्तावित विधेयक के विरोधियों का तर्क है कि खण्डित विनियामक व्यवस्था के स्थान पर एकीकृत तथा केन्द्रीकृत नियामक व्यवस्था, पहले से ही बदहाल उच्चतर शिक्षा के लिए नुकसानदेह है। इससे केंद्रीकरण तथा सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा, संस्थागत स्वायत्तता नष्ट होगी, कर्ज आधारित वित्तीयन के कारण शिक्षा में व्यवसायीकरण बढ़ेगा। इससे उच्चतर शिक्षा में सुधार तो नहीं होगा, बल्कि बौद्धिकता पर सरकारी कब्जा हो जाएगा। विश्वविद्यालय सहित उच्चतर शिक्षा संस्थान परिसर में, शिक्षकों या विद्यार्थियों के मध्य असहमति व्यक्त करने में डर होगा। शिक्षा के निजीकरण तथा उच्चतर शिक्षा के निगमीकरण को बढ़ावा मिलेगा; सरकारी शिक्षा कमजोर होगी तथा उसका स्तर गिरेगा। यह भारतवर्ष की बहुलतावादी संस्कृति तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक होगा, इसके परिणाम शैक्षणिक स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता, सामाजिक समानता तथा लोकतांत्रिक भारत के लिए घातक होंगे।

यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यूजीसी के खत्म होने से, लोक कल्याणकारी राज्य तथा सार्वजनिक वित्तीयन के मध्य संबंध समाप्त होगा, जो सामाजिक तथा आर्थिक समानता के लिए उचित नहीं होगा। शिक्षा मंहगी हो जाएगी, निर्धन विद्यार्थी या तो शिक्षण संस्थान से बाहर हो जाएंगे या कर्ज हेतु मजबूर हो जाएंगे, अक्सर ऐसे ऋण, परिवार पर बोझ बन जाते हैं। मानविकी, समाज विज्ञान, कला, मूलभूत विज्ञान तथा क्षेत्रीय भाषाएं उपेक्षित हो जाएंगी। ऐसे विषय आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्य, सृजनात्मक विचार जैसे जरूरीमानवीय मूल्यों के पोषण करने के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक होते हैं। व्यावसायिक जरूरतें संपूर्ण अकादमिक प्रणाली को बदल देंगी, मूलभूत तथा जरूरी ज्ञान के स्थान पर बाजार आधारित विषय को प्राथमिकता मिलेगी। उच्चतर शिक्षा तक पंहुच घटेगी, ज्ञान-विज्ञान गरीबों की पंहुच से दूर हो जाएगा।

यह भी कहा जा रहा है कि उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में संकट नियामकों की बहुलता के बजाय अन्य कारणों से है। आर्थिक संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण शिक्षकों की कमी, खराब बुनियादी ढांचा, घटिया प्रयोगशालाएं, पुराने पुस्तकालय, खेल सुविधाओं का अभाव जैसी अनेक समस्याओं से उच्चतर शिक्षा जूझ रही है। उच्चतर शिक्षण संस्थान, संसाधनों की कमी के कारण बदहाली में हैं, न कि अपर्याप्त पर्यवेक्षण के कारण। नियमित शिक्षकों की जगह तदर्थ व्यवस्था से बौद्धिक माहौल तबाह हो रहा है। अपर्याप्त वेतन तथा सेवा में असुरक्षा से शिक्षक शोध या शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के प्रति तटस्थ हैं। एक तरफ भारी वित्तीयन वाले आईआईटी तथा आईआईएम हैं, दूसरी तरफ राज्यों में अधिकांश उच्चतर शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें कोई तुलना ही नहीं है। सरकारें वित्तीयन की जिम्मेदारी से बच रहीं हैं, आयोजन व्यय बहुत कम होता है नतीजतन, अकादमिक उत्कृष्टता हेतु जरूरी आधारभूत ढ़ाचे की अपर्याप्तता कारण अकादमिक ठहराव है, यह परिस्थिति संस्थागत स्वायत्तता के लिए खतरनाक है। राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थिति चिंताजनक है। शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, प्रस्तावित निकायों में राज्यों का प्रतिनिधित्व न के बराबर होने से मानक, प्रत्यायन, विनियमन तथा वित्तीयन के मामलों में राज्यों की भूमिका नहीं रहेगी।

ऐसी आशंकाएं, पूर्वाग्रह के कारण आधारहीन तथा काल्पनिक तथ्यों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों की बदहाली की चिंता तथा वर्तमान उच्च शिक्षा नियामकों की कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी में भेद न कर सकने के कारण है। भारत की उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा कारण उच्चतर शिक्षण विनियामक निकायों में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, गैर जिम्मेवार व्यवहार रहा है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, नैक जैसी तमाम नियामक निकायों कीकार्यप्रणाली आरंभ से ही पारदर्शिता तथा जवाबदेही का अभाव के कारण हमेशा संदेह के घेरे में रही हैं, इनके कारनामों से उच्चतर शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, ऐसे निकायों का समर्थन तथा व्यवस्था में सुधार हेतु प्रस्तावितनिकाय का विरोध समझ से परे है। राज्य शैक्षणिक संस्थानों के हालात सुधारने हेतु विशेष प्रयास की अवश्य ही जरूरत है। विचार करना चाहिए कि राज्यों की बात इन निकायों तक पंहुच सके, इस हेतु आवश्यक हो तो राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी हो। प्रस्तावित विधेयक से निश्चित तौर पर उच्चतर शिक्षा नियामक निकायों में शिक्षा तथा शोध को बढ़ावा देने हेतु बेहतर कार्यप्रणाली, पारदर्शिता, जवाबदेही, स्वायत्ता, उत्कृष्ट विनियामक, मानक एवं प्रत्यायन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश भर के शिक्षण संस्थानों में बगैर भेदभाव केसमानता के आधार पर शिक्षण तथा शोध का उच्च मानकों के साथ-साथ अकादमिक उत्कृष्टता एवं समग्र विकास, परीक्षा एवं मूल्यांकन, उद्यमिता एवंनवाचार, समता एवं समावेशन, उच्चतर शिक्षा तक पंहुच, सीखने के परिणामों में स्पष्टता, उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्व-नियामक व्यवस्था एवं स्वायत्तता में मजबूती आएगी। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु ऐसे निकायों की सख्त जरूरत है।

फाइल है, फाइल का क्या?

कटाक्ष

सुरेश उपाध्याय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

'सुनोजी, कल मेहमान आने वाले हैं, लंच में क्या बनाए,' श्रीमतीजी ने सहजता से पूछा।

'दाल-बाटी या दाल-बाफले बना लो,' श्रीमानजी ने कहा।

'दाल तो दोनो में कामन है लेकिन बाटी और बाफले में क्या अंतर है, क्या इनमें भी कोई लिंगभेद है?,' अचानक प्रवेश करते हुए चून्नू ने वार्ता में हस्तक्षेप किया।

'दाल-बाटी के साथ राजस्थान तथा दाल-बाफले के साथ मालवा को जोड़ा जाता रहा है, इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है,' श्रीमानजी ने कहा।

'मैं बताती हूँ - बाटी को सीधे अंगारो पर या ओवन में सेंका जाता है और बाफले को पानी में उबालने के बाद,' श्रीमतीजी ने कहा।

अचानक विषय परिवर्तन के इस मौके का फायदा उठाकर श्रीमानजी अपने काम में लग गए और संवाद के पात्र श्रीमतीजी व चून्नू रह गए।

'मतलब बनाने की विधि में थोडा अंतर है,' चून्नू ने अपनी समझ व ज्ञान का प्रदर्शन किया।

'हाँ, पर इससे स्वाद में अंतर आ जाता है'।

'और अंतर बताइए'

'बाटी कुरकुरी व बाफले नरम होते हैं, बाटी सूखी होने से घी को पी जाती है और बाफला नही पी पाता है तथा घी की मात्रा अधिक होने का अहसास देता है, बाटी में गुड़ / शक्कर व घी मिलाकर चूरमा भी बनाया जा सकता है। और यदि सिंकाई में गडबड हो जाए तो बाटी कड़क व बाफला चिठा होने की सम्भावना रहती है।' इतना कहकर वे श्रीमान की तरफ मुड़ी और उन्हे व्यस्त देखकर हैरत से पूछा, 'अरे, आप क्या करने लग गए?'

'कुछ नहीं, जरा वैसे ही फाइल देख रहा था।'

'कौन सी फाइल?।

'अरे, फाइल है, फाइल का क्या?

'सही सही बताओ - कश्मीर फाइल, केरल फाइल आदि या ऐसी कोई और फाइल, समझ ही नहीं आता है, फिल्म बनाते हैं और नाम फाइल रख देते हैं। सीधी सादी गृहणियों को फाइल देखने का कह दो, बेचारी दफ्तर का काम समझ चुप रहती है और आप मजे से फिल्म देखो, कैसा जमाना आ गया है?,' तनिक आवेश में उलाहना देते हुए श्रीमतीजी ने कहा।

'अरे नहीं, भागवान, ऐसी बात नहीं है,' श्रीमानजी ने बात सम्भालने की कोशिश की।

'तो कोई नई फाइल है क्या, जिसकी चर्चाएं रोज अखबारो व चैनलो में हो रही है?, क्या तो नाम है उसका, 'एप्स्टाइन फाइल', कन्ही तुम्हारा तो कोई कारनामा नही है उस एपस्टाइन फाइल में,' श्रीमती जी ने मजे लेने के अंदाज में कहा।

'मी टू' के आंदोलन में बाल बाल बचे श्रीमानजी को इतने में ही पसीने छूट गए, मन विचलित हो गया, पानी के दो घूंट गटक कर वे खुली हवा में जाने को उठे, दो कदम चले ही थे कि श्रीमतीजी ने कहा - ' जाते जाते कल लंच में बाटी बनानी है या बाफले, यह तो बताते जाओ।'

श्रीमानजी को ऐसे में कुछ सूझा नहीं या क्षेत्राधिकार की कोई पुरानी बहस याद आ गई कि ' जो उचित समझो वो करो,' कहकर तेजी से बाहर निकल गए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बेताल बोला- सम्राट ! एक दिन ऐसा आएगा

व्यंग्य

रामेश्वरम तिवारी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हमेशा की तरह अवंतिका का न्यायप्रिय, जनप्रिय और सर्वजन हितकारी सम्राट विक्रमादित्य ब्रह्म मुहूर्त में नहा-धोकर श्मशान पहुँचा। उसने बेताल को अपने कँधे पर बिठाया ओर चल दिया महाकाल की ओर। तभी बेताल बोला- 'सम्राट ! आज मैं तुम्हें भविष्य में घटित होने वाली राजनीति की कहानी सुनाता हूँ। हमारे इस महान देश में एक दिन ऐसा आएगा जब राजतंत्र की जगह पर जनता का शासन होगा। जनता जिस नेता और उसके दल के उम्मीदवार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करेगी, जिसे अपना बहुमूल्य वोट देगी, वह दल विजयी होगा। पर उम्मीदवारों में कुछ तालीमशुदा और कुछ अक्ल से पैदल क़िस्म के सभासद होंगे। इस व्यवस्था को जनतंत्र कहा जायेगा और जो दल बहुमत हासिल करेगा वहअगले पाँच साल के लिए देश पर शासन करेगा।

और मैं यह भी देख रहा हूँ कि एक दिन जनतंत्र में ऐसा पतन का दौर आएगा कि सालों से 'जनतंत्र के नाम पर राजतंत्र का उपभोग' करने वाले बहुरूपियों के वंश में नालायक, नाकारा और निकम्मा नवाब पैदा होगा जो अपने नन्ययानवे की विजय के नशे में विक्षिप्तों-सा व्यवहार करने लगेगा। कभी प्रधान के जबरन गले पड़ेगा, तो कभी अपने दल के नेता को आँख मारेगा, तो कभी शिव भक्त और तिलकधारी बन जाएगा, तो कभी सभा में विभिन्न धर्मों के देवताओं की फ़ोटो लहराकर खुद को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करेगा, तो कभी मोहब्बत के नाम पर लोगों में नफरत बाँटने का काम करेगा, तो कभी समाज को जातियों के लोगों के बीच विष घोलने की काम करेगा, तो कभी सरकार पर वोट चोरी की अफ़वाह फैलाएगा, तो कभी सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाएगा वगैरह-वगैरह। उसकी मैं-मैं, तू-तू को लेकर सभा का मुखिया किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाएगा।'

इतना कहने के बाद बेताल ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साधी और फिर अपनी धीर, गंभीर वाणी में बोला- 'सम्राट! जबकि तत्कालीन प्रधान का सारा फ़ोकस अपने देश की जनता की भलाई और देश के चतुर्मुखी विकास पर लगा होगा। वह रात को बमुश्किल चार-छः घंटों ही सो पाएगा। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष उसका सम्मान करेंगे और देश-विदेश की जनता उसके स्वागत में पलक पाँवड़े बिछाए खड़ी रहेगी। अपने देश को विश्व-पटल पर एक नई पहचान दिलाएगा। महिलाओं को उनका हक और ग़रीबों के लिए दो जून की रोटी की व्यवस्था करेगा। सैन्य क्षेत्र में दुनिया को देश का लोहा मानने पर विवश कर देगा। पर भूतपूर्व प्रधान का अभूतपूर्व शाहबजादा विदेशों में जाकर देश की बुराई करेगा, लोकमंदिर में खड़े होकर विदेशी ताक़तों के बल पर प्रधान और उसकी शासन व्यवस्था पर झूठे, निराधार और अनर्गल आरोप लगाएगा, उसके अँधभक्त कपड़े उतारकर वैश्विक स्तर के आयोजन में नंगा नाच करेंगे, बात-बेबात पर हंगामा खड़ा करेंगे। सभाध्यक्ष को यार कहकर संबोधित करेगा, उसके चेले-चपाटे मिलकर सदन को पहलवानों का दंगल बनाकर रख देंगे।

सम्राट ! आप तो बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं। 'जरा कृपाकर बताएँ कि ऐसी विषम स्थिति से निपटने और जनतंत्र की गरिमा को बचाए रखने के लिए प्रधान को क्या करना चाहिए? विक्रमादित्य ने पल भर के लिए अपनी आँखें बंद की, विचार मग्न हुए और सिर को धीरे से झटका देकर अपनी मधुर वाणी में बोले- 'बेताल समस्या वाकई बड़ी गंभीर और विकराल है, पर इस दुनिया में सारी समस्या के मूल में यह उजबक मानव है और उसका समाधान भी उसी को निकालना है। फिर भी तुमने पूछा है, तो बतलाए देता हूँ। 'प्रधान को चाहिए कि वह देश-विदेश के नामचीन मनोवैज्ञानिकों की एक टीम गठित कर कुडमगज को दिमाग से दिवालिया घोषित कर हमेशा-हमेशा के लिए आगरा या फिर ग्वालियर भेज देना चाहिए। मेरी दृष्टि में उक्त मुसीबत से निपटने का प्रधान के पास एकमात्र यही माकूल उपाय हो सकता है।' तभी बेताल को थोड़ी दूर किसी बाड़े में मुर्ग़े की बाँग सुनाई दी। उसने सम्राट को टा-टा, बाय-बाय किया और उड़कर श्मशान के उसी पीपल के पेड़ की डाल पर जा बैठा।

दृष्टिकोण

डॉ. सत्यवान सौरभ
लेखक स्तंभकार हैं।

सृजन, सुविधा और नकल की नई संस्कृति

हमारी शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से इस मानसिकता को पोषित करती रही है कि अंक सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, प्रक्रिया नहीं। परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होना, दूसरों की उत्तर पुस्तिकाओं से विचार उठाना, और फिर उसी सफलता का गर्वपूर्वक प्रदर्शन—यह सब समाज में किसी न किसी रूप में स्वीकार्य रहा है। आज वही प्रवृत्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से नई शक्ल में सामने आई है। अंतर केवल इतना है कि अब नकल अधिक चमकदार, अधिक विश्वसनीय और अधिक सुरक्षित दिखाई देती है।

कहा जाता है कि हर नई तकनीक अपने साथ सुविधा लेकर आती है, पर कुछ तकनीकें धीरे-धीरे हमारी सोच और आदतों को भी बदल देती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। उसने लिखने की गति बढ़ाई है, उसे आसान और सुलभ बनाया है; पर उसी अनुपात में उसने सृजन के अर्थ को धुंधला भी किया है। अब प्रश्न यह नहीं रह गया कि 'लिखा कितना अच्छा है', बल्कि यह बन गया है कि 'लिखा किसने है और किस तरह लिखा है।'

जब किसी लेख, कविता या विचार को पढ़ते हुए यह बोध होता है कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा रचा गया है, तो पाठक के भीतर कुछ टूट-सा जाता है। शब्द सधे हुए होते हैं, भाव भी उपयुक्त लगते हैं, पर कहीं एक रिक्तता रह जाती है। जैसे सुंदर शरीर हो, पर उसमें प्राण न हों। रचना का वह जादू, जो लेखक और पाठक के बीच एक अदृश्य संबंध बनाता है, अचानक समाप्त हो जाता है। यह केवल सौंदर्य का नहीं, विश्वास का भी प्रश्न है।

समस्या यह नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिख सकती है। समस्या यह है कि वह लिखते समय मनुष्य होने का भ्रम रचती है। वह अनुभव की नकल करती है, पीड़ा की भाषा बोलती है, प्रेम और करुणा के मुहावरे दोहराती है—बिना कभी असफलता, भय या दुविधा से गुज़रे। जब ऐसी सामग्री किसी मनुष्य के नाम से प्रस्तुत की जाती है, तो वह तकनीकी सहायता नहीं रह जाती; वह बौद्धिक नकल का रूप ले लेती है।

यह नकल कोई नई बात नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से इस मानसिकता को पोषित करती रही है कि अंक सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, प्रक्रिया नहीं। परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होना, दूसरों की उत्तर पुस्तिकाओं से विचार उठाना, और फिर उसी सफलता का गर्वपूर्वक प्रदर्शन—यह सब समाज में किसी न किसी रूप में स्वीकार्य रहा है। आज वही प्रवृत्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से नई शक्ल में सामने आई है। अंतर केवल इतना है कि अब नकल अधिक चमकदार, अधिक विश्वसनीय और अधिक सुरक्षित दिखाई देती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न सामग्री की एक पहचान बन चुकी है—भाषा की दृष्टि से निर्दोष, संरचना में संतुलित, और भावनात्मक रूप से 'उचित'। पर यही परिपूर्णता उसे संदिग्ध भी बनाती है। क्योंकि वास्तविक सृजन प्रायः परिपूर्ण नहीं होता। उसमें झिझक होती है, दोहराव होता है, कभी-कभी असंगति भी होती है। सच्चा लेखक अपने ही विचारों से जूझता है, अपनी ही सीमाओं से संघर्ष करता है। उस संघर्ष की छाया शब्दों में दिखाई देती है, और वही रचना को जीवंत बनाती है।

आज सामाजिक माध्यमों और अंकीय मंचों पर सामग्री की बाढ़ है। हर विषय पर, हर दृष्टिकोण से, तुरंत लेख उपलब्ध हैं। इस भीड़ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तीव्र यंत्र की तरह काम करती है, जो पहले से मौजूद हज़ारों विचारों को जोड़कर एक नया पैकेज बना देती है। यह पैकेज उपयोगी हो सकता है, जानकारीपूर्ण हो सकता है, पर क्या वह दृष्टि दे सकता है? क्या वह जोखिम उठा सकता है? क्या वह यह स्वीकार कर सकता है कि 'मैं गलत भी हो सकता हूँ'?

यहीं मनुष्य और यंत्र के बीच मूल अंतर स्पष्ट होता है। मनुष्य अपनी बात कहते समय डरता है—आलोचना से, अस्वीकार से, असफलता से। और यही डर उसकी आवाज़ को विशिष्ट बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को न आलोचना का भय है, न अस्वीकार का। इसलिए वह सुरक्षित भाषा में लिखती है—सबको स्वीकार्य, किसी को असुविधाजनक न लगे ऐसी। परिणामस्वरूप, हम ऐसी रचनाएँ पढ़ रहे हैं जो सब कुछ कहती हैं, पर वास्तव में कुछ भी नहीं कहतीं।

एक और गंभीर प्रश्न श्रेय का है। यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक औज़ार की तरह उपयोग किया जाए—शोध, संपादन या भाषा-सुधार के लिए—और यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इसमें यंत्र की सहायता ली गई है, तो यह ईमानदारी है। पर जब पूरी रचना यंत्र द्वारा तैयार की जाए और लेखक का नाम किसी मनुष्य का हो, तो यह धोखा है। यह पाठक के साथ भी अन्याय है और सृजन की परंपरा के साथ भी।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि 'अंतिम परिणाम ही महत्वपूर्ण है, तरीका नहीं।' पर यही तर्क नकल को भी वैध ठहराता है। यदि तरीका अप्रासंगिक होता, तो शिक्षा, प्रशिक्षण और अभ्यास का कोई अर्थ न रह जाता। सृजन केवल परिणाम नहीं है, वह एक प्रक्रिया भी है। लिखते समय जो सोच विकसित होती है, जो आत्मसंघर्ष होता है, वही लेखक को गढ़ता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उस प्रक्रिया को बीच में ही काट देती है।

यह कहना भी आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वयं में शत्रु नहीं है। हर तकनीक की तरह उसका मूल्य उसके उपयोग में निहित है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सुविधा, सृजन का स्थान लेने लगती है। जब लेखक बनने के स्थान पर 'सामग्री उत्पादक' बनने की होड़ लग जाती है। जब पहचान मेहनत और अनुभव से नहीं, बल्कि उत्पादन की मात्रा से तय होने लगती है।

भविष्य में संभवतः दो प्रकार के लेखन स्पष्ट रूप से दिखेंगे। एक, जो तेज़ होगा, चमकदार होगा, हर जगह उपलब्ध होगा—और शीघ्र भुला दिया जाएगा। दूसरा, जो धीमा होगा, सीमित होगा, कभी-कभी असुविधाजनक भी होगा—पर टिकेगा। क्योंकि वह किसी मनुष्य द्वारा चुकाई गई कीमत के साथ लिखा गया होगा।

पाठक भी धीरे-धीरे इस अंतर को समझने लगेंगे। वे केवल यह नहीं पूछेंगे कि 'क्या कहा गया', बल्कि यह भी पूछेंगे कि 'किस कीमत पर कहा गया।' रचना की विश्वसनीयता उसके स्रोत से जुड़ जाएगी। लेखक का मूल्य उसके साहस से आँका जाएगा—उस साहस से, जिसे किसी यंत्र से उधार नहीं लिया जा सकता।

अंततः प्रश्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नहीं, हमारी ईमानदारी का है। हम क्या बनना चाहते हैं—सुविधा के उपभोक्ता या अनुभव के सृजनकर्ता? क्या हम अपने नाम के साथ यंत्र की आवाज़ जोड़ना चाहते हैं, या अपनी अधूरी, असुविधाजनक, मानवीय आवाज़ को बचाए रखना चाहते हैं?

सृजन सदैव कठिन रहा है और रहेगा। जो उसे अत्यधिक आसान बना देता है, वह अक्सर उसे खोखला भी कर देता है। इसलिए आज, इस तकनीकी कोलाहल के बीच, सबसे आवश्यक प्रतिरोध यही है कि हम लिखते समय यह स्मरण रखें—शब्द केवल जोड़ने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। और जीवन की सच्ची अनुभूति की नकल कोई भी यंत्र, चाहे वह कितना ही कुशल क्यों न हो, पूर्ण रूप से नहीं कर सकता।

साहित्य

विवेक कुमार मिश्र
लेखक हिंदी के प्रोफेसर हैं।

शिलालेख पर खुदी आत्मकृति सी होती हैं कविताएं

कवि केवल अपने लिए विकल्प रचता है या अपनी मुक्त दुनिया बनाकर रह जाता है वह जीवन पथ पर और संसार में भी लम्बे समय तक नहीं चलता। वहीं पर जब कवि अपने साथ पूरे समाज को लेकर चलता है तो साफ है कि वह एक और ही दुनिया बनाता है जिसमें उसके साथ पूरे समाज को जीने के सूत्र और विकल्प दोनों ही मिलते हैं और इसी तरह से कविताएं बड़ी होती हैं और अपना स्वराज घोषित करती हैं।

कविता आत्मलिपि होती है। एक समय के बाद हर कविता जीवन पर न केवल उतरने लगती है बल्कि जीवन को परिभाषित करने का काम भी कविताएं ही करती हैं। एक कवि कविता में अपनी दुनिया खोजता है, जीवन का पथ और पद अंततः कविता के शिल्प में ही आकार लेता है।

सबसे पहले कविता जीवन को जीने का रास्ता दिखाती है और जहां से जीवन की दुश्वारियां इस तरह से हो जाती हैं कि जीने की दुनिया संभव ही न हो तो कविता विकल्प का संसार भी रचती है। कवि और कवि की दुनिया मूलतः विकल्प की वह दुनिया है जिसमें कवि अपने साथ अपने समाज को लेकर चलता है। यहां यह भी कह सकते हैं कि जो कवि केवल अपने लिए विकल्प रचता है या अपनी मुक्त दुनिया बनाकर रह जाता है वह जीवन पथ पर और संसार में भी लम्बे समय तक नहीं चलता। वहीं पर जब कवि अपने साथ पूरे समाज को लेकर चलता है तो साफ है कि वह एक और ही दुनिया बनाता है जिसमें उसके साथ पूरे समाज को जीने के सूत्र और विकल्प दोनों ही मिलते हैं और इसी तरह से कविताएं बड़ी होती हैं और अपना स्वराज घोषित करती हैं। इस क्रम में कविताएं सभ्यता और संस्कृति का जीवन पथ भी बनाती चलती हैं। कविता की उपस्थिति केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होती न ही किसी कविता का यह लक्ष्य होता है हां कविता मन पर राज करती है और मन पर बहुत दिनों तक इस तरह से पड़ी रहती है कि कविता के प्रभाव से आदमी बाहर निकल ही नहीं पाता उसके सिर पर चढ़कर कविताएं बोलने लगती हैं। यह भी कह सकते हैं कि बोलती हुई कविताओं का राज मनुष्य के उपर इस तरह से होता है कि... बहुत बार लोग इस तरह से बात करते मिलते हैं कि अब तो कविताएं लिखी ही नहीं जा रही हैं या कोई ऐसी कविता नहीं आ रही है जो भक्ति कविता या छायावादी कविता या नई कविता के कवियों जैसा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर छोड़े। इस तरह से यह भी कहते सुनते मिलते हैं कि अब जो लिखा जा रहा है वह समझ में नहीं आता। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लोग-बाग सरल कविता खोज रहे हैं बल्कि यह कहा जा सकता है कि लोग उस कविता को खोज रहे हैं जो उनके दैनंदिन जीवन को आसान बनाने में मदद करें, उनके जीवन का पाठ करें और उनके जीवन में कुछ उपलब्धियों को कविता की शर्तों के साथ जोड़ने का काम करें। जब इस तरह से विचार करते हैं तो साफ है कि आज भी कवि और कविता की उपस्थिति हमारे समाज में उसी ताप और आंच पर पक रहा है, समय के बदलते संदर्भ के साथ कविताओं का पाठ और कविताओं की उस उपलब्धि को सामने रखकर देखने वाले लोगों की जहां कमी है वहीं हम सब कविता को मन मस्तिष्क पर पकने का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। हर कवि लेखक को यह लगता है कि उसके लिखे पर तुरंत प्रतिक्रिया आएं और वह भी प्रशंसात्मक और परिचयात्मक जब इस रूप में कविताओं पर टिप्पणी आने लगती हैं तो तय मानिए कि कवि और कविता के साथ साथ अपने समय की पहचान भी धूमिल हो जाती हैं। इस तरह की टिप्पणी से तात्कालिक सुख मिल सकता है पर आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। कविता की एक पंक्ति यदि आपके मस्तिष्क और हृदय पर एक साथ बजने लगे तो समझ लीजिए कि कविता का आप सहज और स्वतंत्र पाठ कर रहे हैं और वास्तविक रूप में जीवन को जी रहे हैं। कविता और रचनात्मक संसार हमारी दुनिया को जीने का एक तरह से सही सूत्र देने का काम करते हैं। यहां यह भी कह सकते हैं कि सभ्यता, संस्कृति और जीवन क्रम में कविताएं शिलालेख पर खुदी आत्मकृति सी होती हैं। एक क्रम बन जाता है जब जीवन की विस्तारता बातें करने लगती है और रचना के सेतु पर बैठकर हम सब कविता के तार इस तरह से बुनते चलते हैं कि जैसे जीवन क्रम को ही रूप और रंग दे रहे हों। यहां कविता की गति में जीवन की गति ढूढ़ते चलते हैं। मन व संसार की गति के साथ जीवन की ऊष्मा बनाए रखने के लिए कविता की भूमि तैयार होती है। हमारे संसार को सांसारिक सौंदर्य से उठाकर आध्यात्मिक संदर्भ से जोड़ने का काम कविताएं ही करती है। कविताएं आत्मसंसार व आत्मिक दुनिया के व्यवहार को जीवन में लाती हैं। कविता मूलतः आत्म प्रकाश का काम करती हैं। जब सारी दिशाएं खो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है तो कविता ही आत्म प्रकाश बनकर सामने आती हैं। इसीलिए एक कवि के यहां कविता की उपलब्धि आत्म स्वीकार व आत्मलिपि के रूप में होती है। हर कविता सबसे पहले आत्म साक्षात्कार व आत्मलिपि का ही प्रकाश होती है। एक कवि कुछ करें या न करें बस अपने समय के सही सही सवालों को उठाकर रख दें तो भी कवि कर्म सार्थक हो जाता है। यदि वह विकल्प की दुनिया रच देता है तो फिर पूरे युग संदर्भ को वह परिभाषित करने का काम करने लगता है। कवि का आत्मसाक्षात्कार जीवन को जीने का रास्ता देता है। यह संसार एक कवि की आत्मलिपि का साक्षात्कार है। अपने संसार में घूमते हुए सत्य से, जीवन से और आश्चर्य से जहां साक्षात्कार होता है वहां पर कविता सहज ही उपलब्ध हो जाती है। कविता में जीवन पक्ष को खोजना सच में जीवन से साक्षात्कार करना होता है।

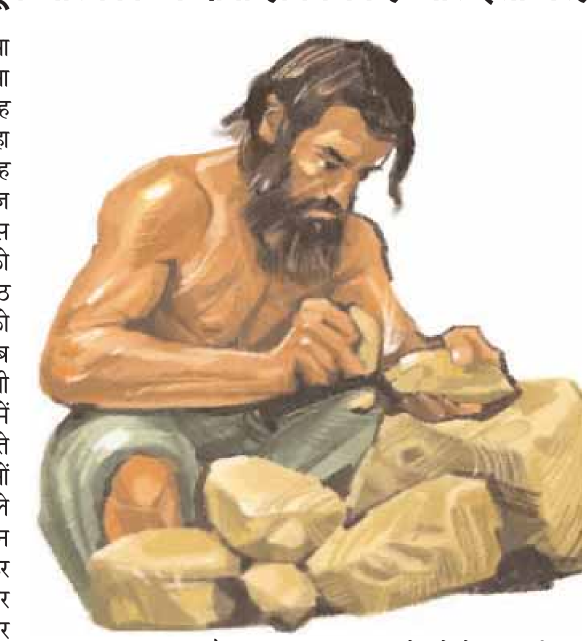

हर कविता समय के साथ, संसार के साथ और जीवन के साथ बतियाना चाहती है। जब आप कविता के संसार में होते हैं तो सच में जीवन जी रहे होते हैं। एक कविता इस तरह से जन्म लेती है कि सामने कुछ न हो फिर भी कुछ होने का, कुछ रचे जाने का भाव बलवती होकर इस तरह से उभर कर आता है कि वहीं जीवन हों। कविता एक आश्चर्यलोक रचती है और वह सब इस जीवन पथ पर ही संभव होता है। जीवन की गतियों, गतिविधियों व संसार भर की उथल-पुथल को एक कवि ही कविता की जड़ों के सहारे थाम कर रखता है। एक कवि की कविता कभी भी केवल उसके जीवन व जीवन संसार का साक्षात्कार नहीं होती बल्कि कवि के यहां जो संसार होता है उसमें सब होते हैं। आजकल एक कवि के यहां दुनिया जो है, उसके परिवार, परिवार की एकरसता और सामाजिक हो जाने के प्रश्न के साथ पूरे समाज से संवाद का वह रूप होता है जिसमें कवि जीवन को जीते हुए ही जीवन और कविता को खोज रहा है। इसीलिए आजकल कविताएं एक खोज की तरह सामने आती हैं। कवि के यहां पूरा संसार इस मायने में होता है कि उसी के रास्ते वह सांसारिक भी हो जाता है और अपनी सांसारिक साधना को जगह भी दे पाता है। कवि जब अपनी दुनिया से बाहर निकल कर समाज में आता है तो समाज उसे एकांत से मुक्त कर जीवन को जीने का बेहतर सूत्र देता है। कविताएं मुक्त करती है और मुक्त मन से संसार पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है। एक तरह से एक कवि की कविता अनंत रूपों में समाज का ही विस्तार लिए होती है।

यादों के झरोखे से

- आरबी त्रिपाठी
लेखक स्तंभकार हैं।

आधी सदी पहले और बाद का एक जीवंत शहर

सत्य नारायण भगवान की कथा में यजमान, पंडित जी को श्रीफल के साथ एक रुपया चढ़ाते थे। एक रुपये के साथ अठन्नी- चवन्नी की भी बड़ी वेल्यू थी। चवन्नी (पच्चीस पैसे) से अखबार और एक प्याली चाय पी जा सकती थी। बिनाका गीतमाला सुनते और चाय की चुस्की के साथ अमीन शाइनी की अनूठी आवाज और शैली श्रोताओं को लुभाती थी।

विस्मृतियां कैसी भी हो सुखद या दुखद वे आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप कितना भी भुलाना चाहें भूलना मुश्किल होता है। एक पुराने गाने 'लहरों की तरह यादें..' की भांति। सोचें तकरीबन पचास साल यानी आधी सदी, एक बीते हुए युग की तरह होती है। सो, कैलेंडर वर्ष 2026 की शुरुआत में एक दिन अकस्मात ही एक शहर शुजालपुर मंडी जाना हुआ। जो 1971 से 1973 और पुनः 1975 से 1978 तक का समय पढ़ाई और जीवन के शुरुआती संघर्ष का साक्षी रहा। अपने गृहनगर (उस वक्त का गांव) में उस वक्त ना तो आठवीं कक्षा के आगे शिक्षा की व्यवस्था थी ना ही सड़क और संचार सुविधा। बारिश के मौसम में यह क्षेत्र पूरी तरह कट-ऑफ रहता था। उस दौर में घोड़ा ही एकमात्र साधन था जिससे दस किलोमीटर दूर चलकर सड़क के दर्शन कर पाते थे। दादाजी के घोड़े का सहारा लेना होता था। कभी-कभार पद यात्रा से यह दूरी तय करना होती थी।

यह जीवंत शहर है शाजापुर जिले का शुजालपुर मंडी। मंडी तथा सिटी के बीच बटा हुआ। मास्टर प्लान के तहत विकसित इस शहर (मंडी) की खासियत थी चौड़ी सड़कें, काफी खुलापन जो स्वास्थ्य के लिये मुफीद था। मकान, प्रतिष्ठान भी सुव्यवस्थित थे तथा अधिक ऊंचाई वाले नहीं थे। लोकल मंडी-सिटी के बीच तांगे चलते थे जो एक रुपया सवारी वसूलते थे। वह भी ज्यादा लगते थे। सत्य नारायण भगवान की कथा में यजमान, पंडित जी को श्रीफल के साथ एक रुपया चढ़ाते थे। एक रुपये के साथ अठन्नी- चवन्नी की भी बड़ी वेल्यू थी। चवन्नी (पच्चीस पैसे) से अखबार और एक प्याली चाय पी जा सकती थी।बिनाका गीतमाला सुनते और चाय की चुस्की के साथ अमीन शाइनी की अनूठी आवाज और शैली श्रोताओं को लुभाती थी। अब अठन्नी चवन्नी बेचारी चलन से बाहर कर दी गई और एक रुपये को पूर्णांक मान लिया गया है। तत्कालीन दौर में किसी की अवमानना करने को चवन्नी करना कहा जाता था।

साल 1971 में शुजालपुर मंडी के प्रतिष्ठित शारदा हायर सेकंडरी स्कूल में 9वीं क्लास में एडमीशन लिया। पूज्य चाचाजी स्व. के. एल. शर्मा के साथ रहकर पढ़ाई के साथ नये तौर तरीके सीखे थोड़ी बहुत दुनियादारी देखी समझी। कुछ समय स्व. श्रीनारायण जी के मकान में तथा बाद में परम वैष्णव भगवान दास चांडक जी के मकान में रहे। भगवान दास जी की पत्नी मां के समान हमारा ख्याल रखती थी। उनके साथ बृजमोहन दास जी की विजय वाटिका जाकर सत्संग सुनने का क्रम बना। साथ ही श्रीराम मंदिर में भागवत के विद्वान पुरुषोत्तम दास महाराज के मुखारविंद से श्रीमद्भागवत पुराण कथा श्रवण की। पढ़ाई गौण होकर आध्यात्म, सत्संग की ओर झुकाव बना। स्कूल के प्राचार्य जी को पता लगा तो स्वाभाविक ही नाराजगी झेलना पड़ी। उन्होंने हमें अखबार, पत्रिकाएं पढ़ने, लाइब्रेरी में समय निकालकर नियमित जाने को प्रेरित किया। उस दौर की दिनमान, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नंदन, पराग, कादम्बिनी, सारिका जैसी उत्कृष्ट पत्रिकाओं से शायद ज्ञान चक्षु खुले तथा हिंदी साहित्य और शब्द भंडार के प्रति झुकाव हुआ।

इस बीच चाचाजी का ट्रांसफर प्रमोशन पर मंदसौर जिले में हो जाने से कुछ समय पढ़ाई में बाधा आई लेकिन वह पोस्टिंग उन्हें रास नहीं आई तथा वे पुनः अपने पूर्व पद पर लौट आये। सब कुछ अच्छा चल रहा था परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई के दौरान दुर्योग से एक एक्सीडेंट में मेरे पैर में फ्रेक्चर हो जाने से सारी गतिविधियां शून्य हो गई। लंबे समय बेड पर रहना, समय काटना मुश्किल हो गया। पूज्य बाबूजी और मां पर जैसे दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। तथापि उन्होंने धैर्य धारण कर मेरी देखरेख की। इससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते।

चुनौतियों से जूझकर आगे की पढ़ाई जारी रखी। जिस समय प्रदेश में परीक्षाओं को लेकर जनरल प्रमोशन का शोर मचा था अपन ने स्नातक द्वितीय की परीक्षा दी तथा अपनी क्लास में उत्तीर्ण होने वाले अपन अकेले थे। इससे कॉलेज में अपनी पूछ परख बड़ गई

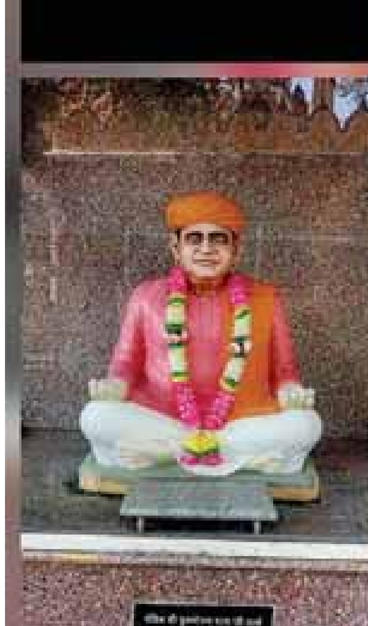

लेकिन अनेक कारणों के चलते 'जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनि जहाज पर आय' की तर्ज पर शुजालपुर मंडी आना पड़ा। अनुज दिनेश और यदुनंदन भी आगे पढ़ाई के लिए यहीं आ गये थे। पूज्य बाबूजी और श्रीनारायण श्रीवास्तव जी के अच्छे संबंधों से हमें उनके मकान में रहने का स्पेस मिला। हमें श्रीवास्तव परिवार से जो संबल, आत्मीयता और अपनत्व मिला वह अवर्णनीय है। कमल भैया, महेंद्र भाई समेत परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिये फिक्रमंद रहे। उस वक्त ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वे मकान मालिक और हम किरायेदार हैं। आज के समय इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रहने की यह जगह पूज्य बाबूजी के पुण्य प्रताप और श्रीनारायण जी के साथ उनके संपर्क से मिली थी इसका हमने सदैव ध्यान रखा।

साल 1977 के आखिर में हम भोपाल पहुंच गये तथा एक समाचार पत्र संस्थान ज्वाइन किया। यह अपने लिये एक अलग दुनिया थी जिससे एडजस्ट होने वक्त लगा। भोपाल पहुंचकर भी कमल भैया और महेन्द्र से संपर्क बना रहा लेकिन बाद में शासकीय सेवा और तबादलों तथा पारिवारिक दायित्व की वज़ह से चाहकर भी मंडी नहीं जा सके।

इस साल की शुरुआत की एक घने कोहरे वाली सुबह जब शुजालपुर मंडी जाना हुआ तो देखा और पाया कि यह शहर समय के साथ कितना बदल चुका है। मास्टर प्लान में बनी चौड़ी-चौड़ी सड़कें सकरी हो गई है। दुकान, प्रतिष्ठान, हास्पिटल की बहुतायत हो गई। रेल्वे स्टेशन जैसा था वैसा ही है। पचास साल में भी भोपाल- इंदौर जाने वाले मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग पर ब्रिज नहीं बनने से रेल्वे फाटक पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। जबकि यहां से एक समय लीलाधर जोशी सीएम पद पर रहे। बाद में विद्याधर जोशी मंत्री रहे और वर्तमान में मंत्रिमंडल में यहां का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय भी बहुत प्रभाव रखते हैं। हमारे स्कूल, कॉलेज के नाम के आगे कुछ विशेषण लगाकर बदल दिया गया है। बाजार बड़ा हो गया लेकिन पुराने लोग इस असार संसार से विदा ले चुके हैं।

दर्जन भर से अधिक बस संचालित करने वाली बृजमोहन दास जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी एक- दो बसों तक सीमित रह गई। वैष्णव और प्रभु श्रीकृष्ण के भक्त इस परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ कि घर परिवार तकरीबन बिखरकर उजड़ गया। विजय वाटिका नाम मात्र को शेष बची। सुस्वादु भोजन के लिये मशहूर रामनाथ तथा जोशी भोजनालय का अता पता नहीं है। धरती टॉकीज जहां अनेक मूवी देखी वो शायद धरती में ही समा गया। भगवान दास चांडक जी की दुकान तथा मकान, संपत्ति उनके जाने के बाद बिक गई। यह सब मेरे लिये बहुत दुखद था। शानदार तांगों की जगह प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों ने ले ली। एक शांत शहर कब का कोलाहल, शोर शराबे तथा ट्राफिक जाम में बदल गया पता नहीं चला।कभी साफ सुथरे शहर में अन्य शहरों की तरह कचरे और पन्नियों के ढेर लगे थे।

यहां का प्रसिद्ध श्रीराम मंदिर ज्यों का त्यों बना हुआ है यह देखकर बहुत सुकून मिला। हां, अलबत्ता श्रीनारायण जी का मकान सुरक्षित बना हुआ है जहां उनका संपूर्ण परिवार एक साथ रहते हुए मिला। सभी भाई इसी मकान में एक साथ निवास करते हैं, यह आज के युग में बहुत कम देखा जाता है । काफी अरसे बाद कमल भैया और महेंद्र भाई से मुलाकात हुई जो स्मरणीय रहेगी। जबकि स्कूल कॉलेज के मित्र सब इधर-उधर हो गये और हमें पढ़ाने वाले आदरणीय गुरुजन भी।

पांच नगर परिषदों में एक भी इंजीनियर नहीं, बैतूल नपा में ईई का पद दो साल से खाली

जिले की निकायों में 24 में से इंजीनियरों के 12 पद खाली

बैतूल। जिले की नगरीय निकायों में इंजीनियरों की कमी है। बताया जा रहा है कि जिले के निकायों में वैसे 24 इंजीनियरों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें से 12 पद खाली है। जिसका असर विकास कार्यों की रफ्तार पर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई नगर पालिका और नगर परिषदों में इंजीनियरों के स्वीकृत पद वर्षों से खाली हैं। इससे न सिर्फ निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि गुणवत्ता की जांच और तकनीकी निगरानी भी कमजोर हो गई है। यहीं कारण है कि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच और देखरेख ठीक से नहीं हो रही है और ठेकेदार भी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे है। कुछ नगरीय निकायों में प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा है। इंजीनियरों की कमी के कारण सड़क, नाली, भवन और विद्युत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। तकनीकी स्टाफ की कमी से निर्माण गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। बैतूल नगरपालिका की बात करे तो यहां एक कार्यपालन यंत्री का पद स्वीकृत है, लेकिन यह पद करीब दो वर्षो से खाली पड़ा है। बैतूल का कार्यपालन यंत्री बैतूल के साथ ही जिले की अन्य नगर पालिका एवं नगर परिषदों के कार्यो की भी देखरेख करते हैं। पद खाली होने के कारण बैतूल सहित जिले की सभी नगरीय निकाय को तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यपालन यंत्री के अन्य कार्यों के लिए भोपाल जाना पड़ रहा है। इसके चलते नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति, तकनीकी अनुमोदन और टेंडर प्रक्रिया में देरी हो रही है। जिसके कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं और गुणवत्ता की भी ठीक से निगरानी नहीं हो पाती है।

प्रभारी इंजीनियरों के भरोसे नगरीय निकाय – जिले की 5 नगर परिषद प्रभारी इंजीनियरों के भरोसे संचालित हो रही है। प्रभारी इंजीनियर इन परिषद में कभी-कभी ही जाते है। वैसे नियमानुसार इंजीनियरों को सप्ताह में कम से कम 2 बार आना चाहिए। लेकिन इंजीनियर महीने में 2 से 4 बार ही आ रहे। नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में इंजीनियर का पद खाली है। बताया जा रहा है कि यहां प्रभारी इंजीनियर महीने में 2 से 3 बार ही आते हैं। इंजीनियरों की कमी के कारण सड़क, नाली, भवन, विद्युत एवं अन्य विकास कार्यों की तकनीकी जांच समय पर नहीं हो पा रही है। कई जगहों पर एक ही इंजीनियर को अतिरिक्त प्रभार दिया है, जिससे काम का दबाव बढ़ गया है और निगरानी कमजोर पड़ रही है। जिसके कारण ठेकेदार मनमानी करते है और मानीटरिंग के अभाव में निर्माण समय से पहले ही खराब हो जाते है।

पांच नगर परिषदों में इंजीनियर ही नहीं– जिले की पांच नगर परिषद इंजीनियरों के अभाव में संचालित हो रही है। बताया जा रहा है कि बैतूल बाजार, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, आठनेर और भैंसदेही नगर परिषदों में सिविल इंजीनियर का पद स्वीकृत होने के बावजूद वर्तमान में एक भी इंजीनियर पदस्थ नहीं है। वर्तमान में मुलताई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को शाहपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सिविल के निर्माण कार्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा देखे जाने से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शाहपुर में करोड़ों की लागत से अमृत 2.0 नल जल योजना का काम चल रहा है, जिसे सिविल की जगह 90 किमी दूर मुलताई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा देखा जा रहा है। वहीं सारनी के इंजीनियर को 100 किलोमीटर दूर भैंसदेही का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वहीं घोड़ाडोंगरी में 90 किलोमीटर दूर मुलताई के इंजीनियर काम देख रहे हैं।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पड़ रहा असर

नगरीय निकायों और परिषदों में इंजीनियरों की कमी का असर सीधे निर्माण कार्यो पर पड़ रहा है। कुछ नगर परिषद का प्रभार जरूर अन्य नगरपालिका के इंजीनियरों को सौंपा गया है, लेकिन निर्माण कार्यो की समय-समय पर सहीं मानीटरिंग नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से निकायों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे है और जनता में भी निर्माण कार्यो में गुणवत्ता की कमी के कारण नाराजगी बनी रहती है। दूसरी तरफ अतिरिक्त प्रभार के कारण इंजीनियरों पर अतिरिक्त कार्य का दबाव पड़ रहा है। जिसका असर यह होता है कि वह प्रभार वाले नगरीय निकायों में नियमित मॉनीटरिंग नहीं कर पाते है और ठेकेदार मनमानी करते है। जिससे नगरीय निकायों में घटिया निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है।

इनका कहना है –

बैतूल सहित जिले की सभी नगरीय निकायों में इंजीनियरों की कमी है। इंजीनियरों की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो रहे है। इंजीनियरों के पद भरने के लिए शासन को डिमांड भेजी गई है।

– **सतीश मटसेनिया,** सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

नगर में बिगड़ती पेयजल व्यवस्था को लेकर पार्षद ने दिया ज्ञापन, चिकना नाला के विस्तार की मांग

आधे से ज्यादा नगर की पेयजल आपूर्ति कर सकता है चिकना नाला

आमला। नगर के सबसे पुराने एकमात्र जल स्रोत चिकना नाला के विस्तारीकरण की मांग को लेकर वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद राकेश शर्मा ने नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्षद ने ज्ञापन में कहा है कि स्थानीय प्रशासन ने बीते कई वर्षों में नगर की पेयजल व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, किंतु फिर भी नगर में पेयजल व्यवस्था को लेकर हालत ज्यादा बदल नहीं पाए हैं। अब ग्रीष्मऋतु शुरू होने को है, ऐसे में हर साल की तरह इस साल फिर जल संकट के आसार नजर आने लगे है। उन्होंने नगरपालिका के दशकों पुराने परंपरागत जल स्रोत चिकना नाला को गर्मियों के लिए एक मजबूत विकल्प बताया है। ज्ञापन में उल्लेख है कि चिकना नाला पर नगरपालिका का पूरा सिस्टम पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन नपा के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान न देने पर चिकना नाला बदहाली की हालत में पहुंच गया है, इस ओर ध्यान देने की मांग ज्ञापन में की गई है। इस मौके पर पार्षद ने नपा परिषद को शीघ्र चिकना नाला का निरीक्षण और इस मामले में त्वरित निर्णय करने की मांग भी नपा अधिकारी से की है।

आधे शहर की आपूर्ति कर सकता है चिकना नाला – जानकार बताते हैं कि पंचवटी हनुमान मंदिर के पास स्थित चिकना नाला आधे से ज्यादा शहर की प्यास बुझा सकता है, किंतु नपा द्वारा चिकना नाला को अलग कर दिया गया है। इस बारे में नगरवासी गजानंद टिकारे, भगवान दास, संजय साहू, राजकुमार सोनी आदि लोगों ने बताया है कि अगर नगरपालिका चिकना नाला को लेकर गंभीरता से काम करें तो शहर में हर साल गर्मियों में पैदा होने वाले जल संकट को काफी हद तक टाला जा सकता है।

होली से 2 दिन के अंतराल में होगी जलापूर्ति – नगरपालिका द्वारा अगले माह 3 मार्च होली से पूरे शहर में दो दिन के अंतराल में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में जल शाखा के प्रभारी अरुण पवार ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए होली से 2 दिन के अंतराल में पेयजल आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है।

600 से ज्यादा नल कनेक्शन भी कटेंगे– नगर पालिका के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे शहर में लगभग 6600 नल जल उपभोक्ता है। बता दें कि बीते लगभग तीन वर्ष पहले पूरे नगर में सभी घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे, किंतु जैसी कि नपा सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें से लगभग 600 से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक नल कनेक्शन की राशि नगर पालिका में जमा नहीं की है। ऐसे में नपा आमला ऐसे नल कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का अभियान भी चला रही है।

छात्रावास अधीक्षक ने वरिष्ठ पत्रकार से की अभद्रता

वीडियो बनाकर किया वायरल, ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग

बैतूल। सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास अधीक्षक द्वारा वरिष्ठ पत्रकार से अभद्रता किये जाने की शिकायत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल से की है। इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें बताया कि सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास के अधीक्षक नारायण नगदे को जारी नोटिस के आधार पर खबर का प्रकाशन किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम सिन्हा ने बताया कि समाचार प्रकाशन का तात्पर्य छात्रावास में

अनुशासन कायम करना एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए था, किन्तु अधीक्षक श्री नगदे द्वारा 23 फरवरी को रास्ते में रोककर छात्रों का स्टेटमेंट लेने के बहाने अपने कक्ष में बुलाकर मेरे साथ अभद्रता की। साथ ही धमकी देने संबंधी छात्रों से वीडियो बनाकर वायरल किया है, जोकि सरकारी कर्मचारी को नहीं किया जाना चाहिए था। पत्रकारों ने उक्त मामले की सूक्ष्मता से जांच कर छात्रावास अधीक्षक नारायण सिंह नगदे पर नियमानुसार कार्रवाई किये जाने की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे।

विद्यार्थियों ने दिल्ली में डाबर इंडिया लिमिटेड की रिसर्च व फैक्ट्री का किया विस्तृत अवलोकन

ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने किया 10 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण

बैतूल। ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भारत भारती जामठी बैतूल के द्वितीय वर्ष सत्र 2023-2024 के छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा 10 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर दिल्ली भेजा गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विश्व की प्रमुख आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड के विभिन्न इकाइयों का विस्तृत भ्रमण एवं अवलोकन किया।

छात्र-छात्राओं ने डाबर रिसर्च फाउंडेशन, डाबर रिसर्च एवं डेवलपमेंट विभाग, डाबर की फैक्ट्री तथा टिशू कल्चर फैसिलिटी का विस्तार से निरीक्षण किया। डाबर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों को संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी और उनकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया। महाविद्यालय के आचार्य डॉ. अमित श्रीवास्तव के विशेष अनुरोध पर इस विजिट को

सुलभ बनाने में डॉ. अजीतपाल सिंह और भुवनेश्वर पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के सेल्स हेड डॉ. रूपेश वरणेकर तथा नेशनल सेल्स हेड डॉ. नितिन बेरड़े ने भी छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन किया। यह 10 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण अध्यक्ष गणेश मालवीय, कोषाध्यक्ष संतोष पाल एवं प्राचार्य डॉ. विजय माने के मार्गदर्शन में तैयार रूपरेखा के अनुसार संपन्न हुआ। समापन अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक डॉ. संदीप खाकरे और डॉ. अमित श्रीवास्तव ने महाविद्यालय प्रबंधन एवं सभी संबंधित संस्थानों का सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

'महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार को बढ़ावा'

जिला स्तरीय जन अभियान परिषद नर्मदापुरम की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

सोहागपुर। जन अभियान परिषद नर्मदापुरम की जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में संभागीय समन्वयक कौशलेंश प्रताप तिवारी एवं जिला समन्वयक पवन सहगल के आतिथ्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर संभागीय समन्वयक कौशलेंश प्रताप तिवारी ने स्वावलंबन के माध्यम से महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं की आय वृद्धि हेतु नवाचार आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। जिससे महिलाएँ आत्मनिर्भर बन सकें। जिला समन्वयक पवन सहगल ने कहा कि सभी नवांकुर संस्थाएँ ग्राम स्तर पर प्रस्फुटन समितियों को सक्रिय करें। नियमित सेक्टर स्तरीय बैठकें आयोजित करें। दीवारों पर लेखन को

प्राथमिकता दें । ग्राम चौपाल के माध्यम से शासकीय योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के सेवा कार्यों को सशक्त बनाने पर बल दिया। इस बैठक में नवांकुर नर्सरी निर्माण, प्रस्फुटन समितियों की सेक्टर स्तरीय बैठकों, समितियों के दस्तावेजीकरण, नवांकुर संस्थाओं द्वारा विगत माह में किए गए कार्यों, प्रस्फुटन समितियों के बोर्ड-फ्लेक्स एवं कार्यालय निर्माण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। प्रस्फुटन समितियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिले में कार्यरत समस्त चयनित नवांकुर संस्थाओं द्वारा विगत एक माह में किए गए कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जन अभियान परिषद मध्यप्रदेश कार्यालय द्वारा निर्धारित दायित्वों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गहन चर्चा की गई। ग्राम चौपाल, सामूहिक श्रमदान तथा ग्राम स्तर पर परिवारों से व्यक्तिगत संपर्क जैसे विषयों पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। बैठक में ब्लॉक समन्वयक नरेंद्र देशमुख, हरिदास दायमा, विवेक मालवीय, किशोर कड़ोले, दयाराम उमरे, सुखवती वर्मा आदि उपस्थित थे। आभार ब्लाक समन्वयक नरेंद्र देशमुख ने व्यक्त किया।

एसआईआर 2026 विशेष गहन पुनरीक्षण

नर्मदापुरम कलेक्टर कार्यालय में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां प्रदान की

हीरालाल गोलानी, सोहागपुर। नर्मदापुरम कलेक्टर कार्यालय के रेवा सभा कक्ष में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन पांडे की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को 1283 मतदान केंद्रों की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की 1-1 मुद्रित प्रति (मतदाताओं के फोटो सहित) प्रदान की गई। इसके साथ सभी मतदान केंद्रों की मतदाता सूची (फोटो रहित) की सॉफ्ट कॉपी (डीवीडी) भी प्रदान की गई। इस अवसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनोखे लाल राजोरिया एवं धर्मेंद्र तिवारी, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र मालवीय, धनीराम गौर एवं सुमेर सिंह प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी के मनोहरलाल बड़ानी एवं प्रशांत दीक्षित एवं बहुजन समाजवादी पार्टी के रामबाबू बरौआ आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। नर्मदापुरम जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया 21 फरवरी को

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जिसमें जिले की चारों विधानसभा के 1283 मतदान केंद्रों पर नियुक्त 1283 बीएलओ, 121 बीएलओ सुपरवाइजर, 4 ईआरओ एवं 12 एईआरओ के माध्यम से संपूर्ण एस आई आर की गतिविधियां संपन्न कराई गईं। पुनरीक्षण कार्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए भी सक्रिय थे जिनमें कांग्रेस के 1152 एवं भाजपा के 1276 बीएलए ने सहभागिता निभाई थी। एस आई आर प्रारंभ होने के समय 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जिले में 9,61,165 मतदाता पंजीकृत थे। प्रथम चरण (गणना चरण) के उपरांत 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की संख्या घटकर 9,21,830 रह गई। प्रथम चरण में 39,335 मतदाताओं के नाम Absent/Shifted/Death/Duplicate होने के कारण हटाए गएथे।द्वितीय चरण (नोटिस, सुनवाई एवं दावा-आपत्ति चरण) में 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्तियां प्राप्त की गईं। इसके साथ ही 05 जनवरी 2026 से 10 फरवरी 2026 तक Unmapped Electors (11,049) एवं Logical Discrepancies वाले 1,64,140, इस प्रकार कुल 1,75,189 मतदाताओं की सुनवाई जिले में पदस्थ 186 ईआरओ एवं एईआरओ ने की ।

दावा-आपत्ति प्रक्रिया के दौरान 15,834 मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि 2,302 नाम हटाए गए। नोटिस एवं सुनवाई के दौरान 405 नाम हटाए गए। इस प्रकार द्वितीय चरण में कुल 2,707 नाम हटाए गए। ड्राफ्ट सूची के पश्चात कुल 13,127 मतदाताओं की शुद्ध (नेट) वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 6,095 पुरुष एवं 7,032 महिला मतदाताओं की वृद्धि शामिल है।

सम्पूर्ण एस आई आर प्रक्रिया के दौरान कुल 42,042 नाम हटाए गए तथा 15,834 नाम जोड़े गए। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 9,34,957 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4,83,804 पुरुष, 4,51,123 महिला एवं 30 अन्य मतदाता शामिल हैं। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान जिले की चारों विधानसभा में फॉर्म 7 के माध्यम से 1407 मतदाताओं के नाम डिलीट हुए।फार्म 8 के माध्यम से 895 मतदाताओं के नाम शिफटेड सूची में डाले गए । इसी के साथ 405 मतदाताओं के नाम डाटा प्राप्त न होने पर हटाए गए ।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतः शिकायतों को नॉन अटेंडेड रखने पर अधिकारियों पर अधिरोपित की जाए पेनल्टी : कलेक्टर सोनिया मीना

सोहागपुर। कलेक्टर सभागार कार्यालय नर्मदापुरम में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने सीएम हेल्पलाइन, नरवाई प्रबंधन, संकल्प से समाधान अभियान के अलावा योजनाओं,अभियानों एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

सोमवार को कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना समय सीमा की बैठक के अवसर पर सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा करके अपने राजस्व, नगरीय निकाय, सामाजिक न्याय सहित अन्य संबंधित विभागों की प्रगति की जानकारी ली । वहीं आपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निराकरण पर प्रारंभ से ही गंभीरता के साथ ध्यान केंद्रित किया जाए। प्राप्त शिकायतों के अनुपात में उनका समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। आपने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए। बैठक में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने नॉन-अटेंडेड शिकायतों पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। आपने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों ने शिकायतों को नॉन-अटेंडेड रखा है। उनको नोटिस जारी करके आवश्यकतानुसार पेनल्टी अधिरोपित की कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में आपने

समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि नरवाई प्रबंधन के संबंध में ठोस एवं प्रभावी कार्य-योजना तैयार की जाए। फसल के अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यकतानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करें । एवं संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

इसी बैठक में आपने ने कृषि विभाग, एसडीएम एवं समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर नरवाई प्रबंधन के लिए उपयुक्त योजना तैयार करें। गेहूं की कटाई के बाद अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए भूसा तैयार किया जाए ।तथा उसके सदुपयोग की भी व्यवस्था की जाए। कृषि अभियांत्रिकी विभाग को भी अपने निर्देश दिए कि नरवाई प्रबंधन में उपयोग होने वाले यंत्रों की सूची उनके धारकों के नाम एवं संपर्क सूत्र सहित तैयार करके पंचायत भवनों, तहसील कार्यालयों एवं अन्य आवश्यक सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाए। जिससे किसानों को यंत्रों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त हो सके।

कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के अवसर पर न्यायालय में लंबित अवमानना प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए जवाब- दावे समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर जवाब प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने न्यायालय के अवमानना प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जवाब की अनुपालन रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति विधि शाखा में अनिवार्य रूप से दर्ज कराई जाए। वहीं फायर एनओसी से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते निर्देश दिए कि लंबित मामलों में विस्तृत प्रकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में संचालित होटल, रिजॉर्ट एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की जांच कर फायर एनओसी तथा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक प्रमाण पत्रों की विधिवत जांच सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में कलेक्टर ने 'संकल्प से समाधान' अभियान की प्रगति की समीक्षा करते निर्देश दिए कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाएं। जिससे शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके।ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने समस्त एसडीएम को अभियान की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ आपने कहा कि अभियान में आयोजित होने वाले शिविरों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। आपने अंत में निर्देशित किया कि सभी विभागों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत समितियों का गठन किया जाए। समिति द्वारा नियमित रूप से बैठक आयोजित करने के साथ कार्यालयीन कर्मचारियों को भी कार्योन्मुख किया जाए। आपने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त संबंध में कार्यशाला आयोजित करके समस्त विभागों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

राजस्व मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री ने सीहोर में किया राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण

राजा भोज केवल आध्यात्मिक चेतना के केंद्र नही थे, बल्कि टेक्नोलॉजी निर्माण के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान है - उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार

राजा भोज केवल एक पराक्रमी राजा ही नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति, न्याय और सुशासन के प्रतीक थे - राजस्व मंत्री श्री वर्मा

सीहोर (निप्र)। राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा तथा उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदरसिंह परमार ने सीहोर में परमार समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज केवल एक पराक्रमी राजा ही नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति, न्याय और सुशासन के प्रतीक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा, साहित्य, जल प्रबंधन, वास्तुकला तथा लोककल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए। राजा भोज ने समाज को यह संदेश दिया कि सशक्त शासन वही होता है जो जनता के हित, ज्ञान के विस्तार और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित हो। उन्होंने कहा कि आज भी राजा भोज की कार्यशैली प्रशासन और जनसेवा के लिए प्रेरणास्त्रोत है। प्रदेश सरकार उनके आदर्शों पर चलते हुए विकास, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदरसिंह परमार ने कहा कि सम्राट राजा भोज भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने शिक्षा और ज्ञान को शासन की आधारशिला बनाया। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना कर विद्वत्ता की नई परंपरा स्थापित की तथा गुरुकुल और शिक्षण संस्थानों को संरक्षण देकर ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथो में युक्तिकल्पतरू और संमृांगढ़सूत्रधार प्रमुख हैं। राजा भोज केवल आध्यात्मिक चेतना के केंद्र नही थे, बल्कि टेक्नोलॉजी निर्माण के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को राजा भोज के ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे बड़ा माध्यम है और राजा भोज की विचारधारा आज भी नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर और संस्कारित भारत निर्माण की दिशा दिखाती है। इस अवसर पर विधायक श्री सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी श्री कपिल परमार, श्री गौरव सन्नी महाजन, श्री विजेन्द्र परमार, श्री सूरज सिंह परमार, शुजालपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बबीता परमार, श्रीमती सरिता परमार, श्रीमती हेमलता परमार, श्री दुर्गादास कटारे, श्री चंदर सिंह परमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी

रेत/गिट्टी का अवैध परिवहन करते 21 वाहन जप्त

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना से प्राप्त निर्देश के पालन में अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के विरूद्ध खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्पूर्ण जिले में कार्यवाही जारी है। खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा तहसील-नर्मदापुरम में 04 डम्परों को रेत का ओवरलोड परिवहन करते जब्त किया गया है। तहसील सिवनीमालवा में 02 डम्पर को रेत एवं 01 डंपर को गिट्टी खनिज का ओवरलोड परिवहन करते जप्त किया गया। तहसील सोहागपुर से 03 ट्रेक्टर ट्राली को रेत खनिज का अवैध परिवहन करते जब्त किया गया है। इसी प्रकार शनिवार 21 फरवरी 2026 को तहसील-नर्मदापुरम में 04 डम्परों को रेत का ओवरलोड परिवहन करते जप्त किया गया है। तहसील सिवनीमालवा में 03 डम्पर को रेत का ओवरलोड परिवहन करते जप्त किया गया। तहसील पिपरिया में 02 डम्परों को गिट्टी का एवं 02 ट्रेक्टर ट्राली को रेत खनिज का अवैध परिवहन करते जप्त किया गया है। उक्त कार्यवाही राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग के गठित संयुक्त दल द्वारा की गयी है। जब्त वाहनों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भोंडवे ने बैतूल में ट्रेचिंग ग्राउंड का किया निरीक्षण

बैतूल ,निप्र। विधायक बैतूल श्री हेमन्त खंडेलवाल की शिकायत पर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संकेत भोंडवे ने शनिवार को बैतूल के गौठाना क्षेत्र स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ट्रेचिंग ग्राउंड की शिकायत की जांच की और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे के संकलन एवं पुनर्चक्रण से संबंधित निर्धारित योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का निरीक्षण करते हुए स्थानीय रहवासियों से आत्मीय चर्चा भी की। रहवासियों द्वारा बदबू की समस्या बताने पर आयुक्त श्री भोंडवे ने नगरपालिका को ट्रेचिंग ग्राउंड में बायो-ट्रीटमेंट कराने के निर्देश दिए, ताकि तात्कालिक रूप से दुर्गंध की समस्या का समाधान हो सके। स्थानीय लोगों ने वायु प्रदूषण, आवारा कुत्तों की समस्या तथा अन्य परेशानियों से भी अवगत कराया, जिस पर आयुक्त ने उचित निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेचिंग ग्राउंड से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षण के बाद कलेक्टर निवास पर विधायक श्री खंडेलवाल ने आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भोंडवे के साथ ट्रेचिंग ग्राउंड के सम्बन्ध में चर्चा की। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि शिकायतों पर कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने विधायक श्री खंडेलवाल के स्थानीय रहवासियों की समस्या पर आश्वस्त किया कि 3 से 4 दिन में ट्रेचिंग ग्रांउड से दुर्गन्ध की समस्या का समाधान करने और 15 दिन के अंदर कचरा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आवारा कुत्तों और मवेशियों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। वहीं भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए स्थाई समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, आयुक्त नगरीय प्रशासन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अक्षत जैन तथा नगर पालिका के अधिकारी उपस्थित रहे।

नर्मदापुरम विधायक की अनुशंसा पर 06 हितग्राहियों हेतु 1 लाख 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता

नर्मदापुरम (निप्र)। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नर्मदापुरम विधायक डॉ सीतासरन शर्मा की अनुशंसा पर कलेक?टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा विधायक स?वेच?छानुदान निधि से 06 हितग्राहियों के लिए 1 लाख 10 हजार रूपये की प्रशासकीय स?वीकृति जारी की गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप?त जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम विधायक डॉ सीतासरन शर्मा की अनुशंसा पर विधायक निधि से इटारसी निवासी श्रीमती रोशनी कोरी को उपचार हेतु 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार इटारसी निवासी श्रीमती अनुसुइया, श्री गौतम चोरे, श्रीमती नीति जैन, श्री गौरव दीक्षित एवं श्री बलदेव मास्के को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इटारसी तहसील में नापतौल उपकरणों के सत्यापन हेतु विशेष शिविर आयोजित

■ 36 उचित मूल्य दुकानों ने कराया उपकरणों का सत्यापन

नर्मदापुरम (निप्र)। विधिक मापविज्ञान (नापतौल) विभाग, नर्मदापुरम के प्रभारी सहायक नियंत्रक श्री सलिल ल्यूक द्वारा गत सप्ताह इटारसी तहसील अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों (सोसाइटियों) में उपयोग किए जा रहे नापतौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में इटारसी क्षेत्र की 14, सुखतवा की 12, केसला की 06 तथा पथरोटा की 04 उचित मूल्य दुकानों द्वारा अपनी-अपनी संस्थाओं में उपयोग किए जा रहे नापतौल उपकरण शिविर में प्रस्तुत कर सत्यापन कार्य संपन्न कराया गया। इस प्रकार कुल 36 उचित मूल्य दुकानों ने शिविर का लाभ उठाया। प्रभारी सहायक नियंत्रक श्री सलिल ल्यूक ने बताया कि जिन उचित मूल्य दुकानों द्वारा अभी तक सत्यापन कार्य नहीं कराया गया है वे शीघ्र ही नापतौल कार्यालय, नर्मदापुरम में संपर्क कर अपने संस्थान में उपयोग किए जा रहे समस्त नापतौल उपकरणों का सत्यापन कार्य पूर्ण कराएं।

ग्राम लसूडिया परिहार में एनएसएस छात्र इकाई द्वारा 07 दिवसीय शिविर आयोजित

सीहोर (निप्र)। सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) छात्र इकाई द्वारा ग्राम लसूडिया परिहार में 07 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान, श्रमदान, पर्यावरण संरक्षण, जनजागरूकता रैली तथा सामुदायिक संवाद जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ग्रामवासियों को जागरूक किया। समापन अवसर पर प्राचार्य डॉ. रोहिताश्व कुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करती है। प्रभारी प्राचार्य डॉ. शीलचंद गुप्ता ने कहा कि एनएसएस व्यक्तित्व के विकास का सशक्त मंच है। कार्यक्रम में एनएसएस के स्वयंसेवक श्री राहुल राजपूत एवं स्वयं सेविका सुश्री दीक्षा चौरसिया भी शामिल हुए। सुश्री दीक्षा चौरसिया को हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'विकसित भारत युवा कनेक्ट' कार्यक्रम के अंतर्गत 'यूथ आइकन' के रूप में चयनित किया गया है। समापन अवसर पर स्वयंसेवकों को प्रमाण-पत्र, शील्ड एवं मेडल वितरित किए गए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राध्यापकगण सहित स्टॉफ के सदस्य एवं एनएसएस के स्वयंसेवक उपस्थित थे।

उन्नत उद्यानिकी तकनीक सीखने उत्तरप्रदेश रवाना हुए तीस कृषक

जिपं अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया

विदिशा (निप्र)। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना अंतर्गत विदिशा जिले के कृषकों को उन्नत उद्यानिकी तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के 30 कृषकों का दल 22 से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भ्रमण कर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। कृषक दल को आज रविवार को जिला पंचायत परिसर से जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी, जनपद पंचायत नटेरन की कृषि स्थायी समिति के सभापति श्री गजेन्द्र सिंह राजपूत व अन्य जनप्रतिनिधियों तथा उघानिकीय विभाग के सहायक संचालक श्री एस एल सोलंकी द्वारा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। सहायक संचालक श्री सोलंकी ने बताया कि कृषक दल प्रशिक्षण के दौरान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिट्रस, झांसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, रहमानखेड़ा लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमैटिक प्लांट्स, लखनऊ, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में पंजीकृत मलिहाबाद स्थित नर्सरियों तथा आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज अयोध्या का भ्रमण करेंगे। भ्रमण स्थानों पर कृषकों को फल, सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित फसलों की उन्नत किस्मों, पौध उत्पादन, आधुनिक प्रबंधन तकनीकों एवं उद्यानिकी आधारित स्वरोजगार के संबंध में व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी। इस प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी रामचंद्र वर्मा को दल प्रभारी के रूप में अधिकृत किया गया है, जो कृषकों को प्रशिक्षण के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कृषक अपने-अपने क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उद्यानिकी फसलों का विस्तार करेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा जिले में उद्यानिकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह कार्यक्रम कृषकों के कौशल विकास एवं कृषि आधारित आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

केंद्रीय मंत्री श्री उईके, प्रभारी मंत्री श्री पटेल और विधायक श्री खंडेलवाल ने 'मन की बात' कार्यक्रम का किया श्रवण

बडोरा में बड़ी एलईडी पर सुनी गई 'मन की बात

बैतूल (निप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'मन की बात' कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण रविवार को बडोरा में किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया गया, जहां बड़ी संख्या में नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, प्रभारी मंत्री एवं मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्य श्री सुधाकर पवार, पूर्व विधायक श्री शिव प्रसाद राठौर, सरपंच श्रीमती सविता धुर्वे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुंबई में आयोजित Ai Summit का उल्लेख करते हुए अमूल के बूथ पर प्रदर्शित तकनीकी नवाचारों के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी प्रबंधन में एआई की उपयोगिता तथा भारतीय पांडुलिपियों और प्राचीन ज्ञान के संरक्षण में आधुनिक तकनीक के योगदान को रेखांकित किया। आगामी होली पर्व की शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को जनभागीदारी का अभियान बनाकर स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने का भी आह्वान किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ाया।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ग्राम पचामा में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम में हुए शामिल

सीहोर (निप्र)। राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा सीहोर जिले की ग्राम पंचायत पचामा में आयोजित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों के साथ प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम का श्रवण किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को प्रेरणादायक विचार, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होते हैं।

जिला अस्पताल हरदा में होप टी 1 डी पीयर सपोर्ट ग्रुप कैंप सम्पन्न

हरदा ,निप्र। जिला अस्पताल हरदा में शनिवार को होप टी 1 डी नाम से एक पीयर सपोर्ट ग्रुप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जिले भर से टाइप 1 मधुमेह से प्रभावित बच्चे, किशोर, वयस्क और उनके अभिभावक शामिल हुए। इस कैंप का उद्देश्य टाइप 1 मधुमेह से प्रभावित लोगों को एक मंच प्रदान करना था, जहाँ वे एक-दूसरे से बातचीत कर सकें, अपने अनुभव साझा कर सकें और इस बीमारी के प्रबंधन के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर सकें। इस सत्र का संचालन सुश्री ज्योत्सना रंगीन ने किया, जो पिछले 10 वर्षों से टाइप 1 मधुमेह के साथ जीवन जी रही हैं। उन्होंने टाइप 1 मधुमेह की मूल जानकारी, नियमित रूप से इंसुलिन लेने का महत्व, ब्लड शुगर की नियमित जाँच और स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने के बारे में बताया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन यात्रा भी साझा की और बताया कि कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ इस बीमारी को नियंत्रित करना सीखा। उनके अनुभव ने प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को प्रेरित किया तथा उनकी शंकाओं का समाधान करने में मदद की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच. पी. सिंह भी इस सत्र में उपस्थित रहे। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जिला हरदा टाइप 1 मधुमेह से प्रभावित लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और नियमित फॉलो-अप सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। होप टी 1 डी जैसे पीयर सपोर्ट कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाने, उपचार के प्रति नियमितता बनाए रखने और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनसीडी नोडल अधिकारी जिला अस्पताल हरदा डॉ. शैलेन्द्र ठाकुर ने टाइप 1 मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए समय पर निदान, नियमित फॉलो-अप और निरंतर परामर्श बहुत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय में जागरूकता बढ़ाना और टाइप 1 मधुमेह से प्रभावित लोगों के लिए सहयोग प्रणाली को मजबूत करना कार्यक्रम की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

स्पॉन्सरशिप योजना से अवंतिका चौहान के बच्चों की उम्मीदों को मिली नई उड़ान

संकट की घड़ी में स्पॉन्सरशिप योजना बनी सहारा

सीहोर (निप्र)। गरीबी और विपत्तियां जब जीवन के द्वार पर दस्तक देती हैं, तब सरकारी योजनाएं यदि संवेदनशीलता से लागू हों, तो वे किसी देवदूत से कम नहीं होतीं। ऐसी ही एक जनकल्याणकारी योजना है स्पॉन्सरशिप योजना। जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाई जा रही है। स्पॉन्सरशिप योजना, सरकार की एक संवेदनशील और व्यावहारिक पहल है, जो बच्चों को उनके परिवार में ही सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है। सीहोर निवासी श्रीमती अवंतिका चौहान भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं जिनके दो बेटों को इस योजना का लाभ मिला है। श्रीमती अवंतिका चौहान कहती हैं कि उनके जीवन में अचानक अंधकार तब छा गया, जब एक सड़क हादसे में उनके पति का निधन हो गया। घर चलाने वाले का साया उठ गया और दो छोटे बेटों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का क्या होगा। जब सभी रास्ते बंद से लगने लगे, तभी उन्हें अपने वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से इस योजना की जानकारी मिली। उन्होंने आवेदन किया और कुछ ही समय बाद उनके दोनों बेटों को दो-दो हजार रूपये प्रतिमाह मिलने लगे। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से श्रीमती अवंतिका के दोनों बेटों की पढ़ाई को नई दिशा मिली। उनके दोनों बेटे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और मन लगाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। श्रीमती अवंतिका चौहान कहती हैं कि यह योजना सिर्फ सहायता राशि नहीं देती, यह टूटे हुए परिवारों को फिर से खड़े होने की ताकत भी देती है। इस योजना के लिए श्रीमती अवंतिका चौहान ने मुख्यमंत्री श्री डॉ मोहन यादव एवं प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है।

क्या है स्पॉन्सरशिप योजना

यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एक योजना है। यह योजना गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे उन बच्चों के लिए संचालित की जा रही है जिनके माता-पिता नही हैं अथवा माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया है तथा जिनके पास भरण-पोषण या शिक्षा का कोई स्थायी साधन नही है। इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक बच्चे को दो हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के लिए जिले की बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आवेदन किया जाता है। इसके पश्चात घर की स्थिति की जांच की जाती है तथा पात्र पाए जाने पर योजना स्वीकृत होती है और राशि मिलना प्रारंभ होती है।

विधानसभा सत्र में सीएम का ऐलान

उड़द पर 600 रू. प्रति क्विंटल बोनस, भगोरिया बनेगा राष्ट्रीय पर्व

जनजातीय क्षेत्रों में होगी सरकार की पहली कृषि कैबिनेट

भोपाल (नप्र)। विधानसभा के बजट सत्र का आज सातवां दिन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में कहा कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगोरिया लोकपर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय बहुल जिलों बड़वानी, धार और झाबुआ में सरकार कृषि कैबिनेट करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भगोरिया पर्व के दौरान ही कृषि कैबिनेट की बैठक की जाएगी। इधर, सीएम ने बताया कि किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं, सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। सरसों उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

ध्यानाकर्षण में उठा जमीन बंदोबस्त का मामला

विधानसभा में कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने खरगोन के भीकनगांव, झिरन्या और महेश्वर क्षेत्र में जमीन बंदोबस्त नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी से लोगों को परेशानी हो रही है।

कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने भी समर्थन किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि गड़बड़ी हो तो कलेक्टर या तहसीलदार को आवेदन दें, जांच कर सुधार किया जाएगा। सोमवार को लाड़ली बहना योजना और ट्रेड डील को लेकर हंगामा हुआ था।

नगरीय विकास, जनजातीय कार्य, स्कूल, शिक्षा, परिवहन, उच्च शिक्षा पर चर्चा

प्रश्नकाल, शून्यकाल, याचिकाओं की प्रस्तुति और पत्र पटल पर रखने के बाद विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए करीब पौने आठ घंटे का समय तय किया गया है।नगरीय विकास और आवास विभाग पर सोमवार को चर्चा नहीं हो सकी थी, इसलिए सबसे पहले इसी पर चर्चा होगी। इसके बाद जनजातीय कार्य विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग पर चर्चा होगी। लोक परिसंपत्ति विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर भी विधायक अपनी बात रखेंगे। लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग पर भी चर्चा तय है। स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर भी पक्ष और विपक्ष अपनी राय देंगे।उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग और तकनीकी शिक्षा पर भी चर्चा होगी।कौशल विकास और रोजगार विभाग की अनुदान मांगों पर भी सदन में विचार किया जाएगा।

लाड़ली बहना योजना को लेकर हुआ था हंगामा- लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन को लेकर भी सोमवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सवाल उठाया कि योजना के तहत पात्र नई बहनों का पंजीयन कब शुरू होगा, इस बारे में सरकार कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है।

इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री तो सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन पहले यह बताया जाए कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बहनों से क्या कह रहे हैं?

- ग्रीष्मकालीन मूंग से कैंसर बढ़ने की आशंका के बाद सरकार ने मूंग की जगह उड़द को बढ़ावा देने का फैसला किया।
- वर्तमान में उड़द का एमएसपी 7800 रुपए प्रति क्विंटल, बोनस जोड़ने पर किसानों को अधिक लाभ।
- उड़द का रकबा 3 लाख हेक्टेयर बढ़ने की संभावना, कुल 5 लाख हेक्टेयर लक्ष्य।
- किसान कल्याण वर्ष के तहत 5 योजनाओं को कुल 10493.60 करोड़ रुपए की मंजूरी।
- सोयाबीन के लिए 1500 करोड़ की भावांतर योजना के बाद अब सरसों खरीदी पर भी भावांतर योजना लागू होगी।
- खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन के तहत 3285.49 करोड़ रुपए स्वीकृत (5 वर्ष के लिए)।
- पीएम कृषि सिंचाई योजना ('पर ड्रॉप मोर क्रॉप') के लिए 2293.97 करोड़ रुपए मंजूर।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 2008.68 करोड़ रुपए स्वीकृत।
- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 1011.59 करोड़ रुपए की सहायता।
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत 1793.87 करोड़ रुपए की निरंतरता मंजूर।
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस।
- पंचायतों के माध्यम से जी रामजी योजना के तहत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था मजबूत करने का निर्णय।

जयवर्धन सिंह बोले- प्रदेशभर में लागू हो इंदौर मॉडल

नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर देश में सबसे आगे है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में स्वच्छता के लिए दी गई राशि खर्च नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को स्वच्छ बनाने के लिए इंदौर मॉडल लागू किया जाना चाहिए। नगर छोटा हो या बड़ा, यदि इंदौर मॉडल के तहत विकेंद्रीकरण कर घर-घर से कचरा एकत्र कर उसका उचित निष्पादन किया जाए, तो प्रदेश में एक बड़ा संदेश जाएगा। जयवर्धन ने बैंकों के साथ टाई-अप कर मॉडल सिटी के कॉन्सेप्ट पर काम करने की भी बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो तभी सफल होगी, जब उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जाएगा।

भोपाल में मास्टर प्लान जारी नहीं होने पर उठे सवाल

जयवर्धन सिंह ने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान जारी नहीं होने का असर हर नागरिक और व्यवसाय करने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। उन्हें टीएनसीपी और भोपाल के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जहां पूरा लेन-देन का काम होता है।उन्होंने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान लगभग 20 साल से लंबित पड़ा है। अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के कारण 22 करोड़ रुपए का टेंडर बढ़कर 72 करोड़ रुपए का हो गया है।

सीएम बोले- राहुल गांधी रबी, खरीफ, दलहन, तिलहन की फसल बढ़ाने का सुझाव दें

सीएम ने कहा- नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, अगर वह किसान चौपाल में किसानों की बात करें तो अच्छा है। रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, दलहन, तिलहन में कौन-कौन सी फसल हो...उसे किस प्रकार बढ़ावा दें...उस पर सुझाव दें...दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बताएं तो अच्छा होगा।

डेढ़ माह में 10 किलोमीटर नहीं पहुंचा ट्रक ! साढ़े छह लाख रुपए का धान गायब, किसान परेशान

उमरिया (नप्र)। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं। इस बार मामला धान उपार्जन से जुड़ा हुआ है। जिले में 44 खरीदी केंद्रों के माध्यम से 25522 किसानों से 16 लाख 18 हजार 244 क्विंटल धान की खरीदी की गई, जिसमें गोदाम एवं कैंप स्तर पर 6 केंद्र बनाए गए थे। वहीं, 38 केंद्र समिति स्तर पर खुले में खरीदी हुई थी। उन जगहों पर खरीदी गई धान का परिवहन करने के लिए छतरपुर के परिवहनकर्ता पारस जैन को नियुक्त किया गया था।

वाहनों में अनिवार्य है जीपीएस

इस वर्ष प्रदेश सरकार ने धान परिवहन में प्रयुक्त वाहनों में जीपीएस अनिवार्य किया था। सभी वाहनों में लगाया भी गया था। वहीं, जब कोई भी ट्रक धान लोड करने जाता था तो उसकी टीसी कटने से पहले परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के मोबाइल में ओटीपी आती थी। बिना ओटीपी के धान नहीं लोड हो सकती थी।

एक ट्रक धान गायब

इतनी सुरक्षा के बाद परिवहनकर्ता पारस जैन और उनके प्रतिनिधि भोलू अग्रवाल मिलकर 550 बोरी धान अर्थात एक ट्रक गायब कर दिए। इसका आज तक पता नहीं है। सारे मामले का खुलासा, तब हुआ जब धान खरीदी केंद्र नौगमा के किसान धान के पैसों के लिए खरीदी प्रभारी के पास चक्कर लगाने लगे, तब खरीदी प्रभारी अभय चतुर्वेदी भी पता लगाने लगे कि हमने सभी किसानों का धान गोदाम में भेज दिया लेकिन 7 जनवरी को भेजी गई तीन किसानों की 220 क्विंटल धान का भुगतान नहीं हुआ।

उमरियाजिले में खरीदी केंद्र नौगमा के प्रभारी अभय चतुर्वेदी ने बताया कि दिनांक 07/01/2025 को ट्रक क्रमांक एम पी 04 जेड यू 7266 में टी सी क्रमांक 59341080045 के माध्यम से 550 बोरी यानी 220 क्विंटल धान परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि भोलू अग्रवाल के द्वारा ओटीपी बताने के बाद हमारे सेंटर से लोड करवाया गया। उसमें तीन किसानों लालमणि सिंह, विनीता पटेल और राजेंद्र पटेल की धान रही, जिनकी पेमेंट आज तक नहीं हुई। हर जगह पता लगाने के बाद मेरे द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभारी जिला प्रबंधक रोहित सिंह बघेल के यहां 16 फरवरी को लिखित में सूचना दे दी है कि मेरे किसानों का भुगतान करवाया जाए। वहीं, इस मामले में वेयर हाउस की जिला नोडल अधिकारी लक्ष्मी मरावी ने कहा कि इस नंबर की टीसी का माल और इस नंबर की गाड़ी हमारे जिले के किसी गोदाम और ओपन कैंप में आज तक नहीं आया। न ही मेरे को जानकारी है।

मामा-भांजे ने जेल में बनाई गैंग-11...किन्नर-गुरु के घर डकैती डाली

मुरैना (नप्र)। मुरैना के अंबाह में किन्नर के घर हुई डकैती के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वारदात को मामा-भांजे की जोड़ी ने अंजाम दिया था। मामा-भांजे ने जेल में मिले 9 अन्य लोगों को इसमें जोड़ा और पांच दिन में तीन जगह हाथ आजमाया। दो बार बदमाश नाकाम रहे, लेकिन तीसरी बार अंबाह में किन्नर के घर डकैती डालकर फरार हो गए। डकैतों ने बंधक बनाकर अश्लील हरकतें भी की थीं। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए और फरार सभी आरोपी पहले भी मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वारदातों में शामिल रहे हैं। अब तक भांजा सुनील निषाद सहित 5 बदमाश गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं मामा सुरेश निषाद समेत 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह में शामिल 11 में से 9 आरोपी निषाद समाज से हैं, जबकि दो मुस्लिम और तोमर युवक भी इस गैंग का हिस्सा है।

4.77 लाख रुपए में 'यूरोप विद यूके' टूर

16 दिन में 7 देशों की सैर, आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया यूरोप का स्पेशल पैकेज

इंदौर (नप्र)। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने जून में 15 रात और 16 दिन का अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज 'यूरोप विद यूके' लॉन्च किया है। यह यात्रा 9 जून से शुरू होगी। इंदौर और भोपाल से यात्रियों को दिल्ली लाया जाएगा, जहां से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के जरिए टूर संचालित होगा।

आईआरसीटीसी के अनुसार, इंदौर और भोपाल से यात्रियों को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली से सभी यात्री एक साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ान के जरिए यूरोप के लिए रवाना होंगे। मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी गई।

सात यूरोपीय देशों का भ्रमण कार्यक्रम

इस पैकेज में यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली की यात्रा कराई जाएगी। यात्रियों को एक ही टूर में इन सात देशों के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।

आईआरसीटीसी के वेस्टर्न जोन के पीआरओ ए.के. सिंह ने बताया कि यात्रा के दौरान लंदन आई, एफिल टॉवर, लूव्र संग्रहालय, माउंट टिटलिस, लुसेर्न झील, राइन फॉल्स, वेटिकन सिटी और कोलोसियम का भ्रमण कराया जाएगा। कई स्थानों पर क्रूज राइड भी कराई जाएगी।

शिवपुरी में बस-ट्रक की टक्कर

दोनों वाहनों के चालक केबिन में फंसे बस ड्राइवर की मौत, पांच यात्री घायल

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में एनएच-46 पर मंगलवार सुबह 5:30 बजे एक सड़क हादसा हो गया। पूरनखेड़ी गांव के पास आगरा से इंदौर जा रही संजय ट्रेवल्स की बस और एक ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर आपस में फंस गए।

हादसे के बाद दोनों वाहनों के चालक अपने-अपने केबिन में फंस गए थे। क्रेन की सहायता से बस और ट्रक को अलग किया गया, जिसके बाद चालकों को बाहर निकाला जा सका। इस दुर्घटना में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक का उपचार जारी है।

घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया- बस में सवार पांच यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। हादसे के कारण एनएच-46 पर करीब साढ़े तीन घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य कराया।जाम में फंसे स्कूली छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए टोल प्लाजा के पिकअप वाहन का उपयोग किया गया।

यहां पहले भी हो चुके हादसे- स्थानीय लोगों के अनुसार, पूरनखेड़ी के मोहराई गांव के पास ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण सड़क को वन-वे कर दिया गया है। हालांकि, वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए स्पष्ट योजना और संकेतक उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस स्थान पर पहले भी एक बस सहित पांच हादसे हो चुके हैं। कोलारस थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने बताया कि हादसे में मृत बस चालक का शव कोलारस मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पांच घायल यात्रियों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है।

रीवा में आरोपी के गहने पुलिस ने दबाए

वर्दी में 'चोरी' करने वाले थाना प्रभारी समेत दो कॉन्स्टेबल सस्पेंड

रीवा (नप्र)। सिवनी हवाला कांड की तरह ही एक मामला रीवा में सामने आया है। नशीली सिरप की कार्रवाई के दौरान मनगवां पुलिस ने खेल कर दिया। जब्त सामानों की लिस्ट बनाने में हेराफेरी की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सोने के गहने बरामद किए थे। इसी को थानेदार और अन्य पुलिसकर्मियों ने मिलकर दबा लिया है।

खुलासे के बाद बड़ी कार्रवाई

पुलिसकर्मियों की करतूत सामने आने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। इसके बाद थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह धाकड़, कॉन्स्टेबल विजय यादव और बृजकिशोर अहिरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

गहने का किया बंदरबांट

दरअसल,रीवा जिले के मनगवां थाना के थाना प्रभारी अपने खास लोगों के साथ मिलकर जब्त सामनों आपस में बांट लेते थे। इसमें सोने-चांदी के गहने से लेकर रुपए तक शामिल है। मनगवां पुलिस ने 11 फरवरी के एक एसयूवी जब्त की थी। 31 शीशी नशीली सिरप जब्त की गई थी। साथ ही सुभाष मिश्रा और राहुल तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपियों के घर गई और वहां तलाशी ली।